लखनऊ

बुधवार, 26 अगस्त , 2026

वर्ष : 12 । अंक: 2

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

दूसरों की सफलता से मत जलो, मेहनत करो और अपनी अलग पहचान बनाओ।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

यूपी में हुई 3572 नियुक्तियां: सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र, किया एलान- छह महीने में देंगे एक लाख नौकरियां

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। यूपी में कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित युवाओं को मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया।

कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 3446 पदों, जबकि मंडी परिषद में मंडी सचिव के 126 पदों पर चयन प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। दोनों विभागों के चयनित कार्मिकों को समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मौजूदगी रही।

इस मौके पर सीएम योगी ने सबसे पहले नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी। फिर कहा कि आज के दिन पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पूरी करना अपने आप चैलेंज है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सभी का चयन किया जाए, यह चैलेंज है, लेकिन हमारे भर्ती आयोग यह सफल रूप से कर रहे हैं। पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा सरकार की यह उपलब्धि है। 9.30 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है।

पहले की सरकारों में बेटी सुरक्षित नहीं थी। किसान चिंतित थे। ट्यूबवेल की मोटर कब चोरी हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। आज चोरी करने वालों को पता है कि यदि चोरी की तो अगले दिन लंगड़ा हो जाएगा। आज यूपी की प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में युवाओं ने साथ दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमें मिला है। आज बिना किसी पैसे के लेनदेन के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। इसी का परिणाम है कि यूपी बीमारू राज्य से बाहर निकला है।

पहले युवाओं की उपेक्षा होती थी। कोई सरकार ये चाहे कि युवाओं की उपेक्षा करके प्रदेश को आगे बढ़ाए तो संभव नहीं है। आज पहचान का संकट नहीं है। 19, 20, 21 अगस्त को जापान के 240 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी का दौरा किया। पहली बार इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत के अंदर आया। भारत में भी यूपी आया। उन्होंने कहा कि हम यूपी के युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था। 5 हजार से अधिक युवाओं को हमने इस्राइल भेजा। आज वह 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे। घर को पैसे भेजते हैं। आज दुनिया यूपी के युवाओं को मांग रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ

पहले की सरकार ने नकल को जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया था

सीएम ने कहा कि भर्ती बोर्डों से भी कहता हूं कि भर्ती की समय सीमा को और कम कीजिए। पहले यूपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में तीन महीने लगते थे। अगले तीन महीने परिणाम आने में लगते थे। करीब तीन महीने पर्व और त्योहारों में निकल जाते थे। सिर्फ तीन महीने ही पढ़ाई होती थी। पहले की सरकार ने नकल को जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया था। इसी कराण पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।

सपा-बसपा ने चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया था

पहले एक सप्ताह दिन में एक सप्ताह रात में बिजली आती थी। हमने रायबरेली में पूछा कि चलो देते तो थे, वहां लोगों ने बताया कि सिर्फ तीन घंटे बिजली मिलती थी। आज हम किसान को फ्री बिजली दे रहे हैं। पहले किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। सपा-बसपा ने 30 चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया था। पहले एक चीनी मिल को सिर्फ तीन करोड़ में बेच दिया गया था। हमने सांसद रहते उस माफिया को मिल को हासिल नहीं करने दिया।

यूपीआई के एक दशक पूरे, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अनुभव साझा करने का किया आग्रह

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले एकीकृत भुगतान अंतरफलक (यूपीआई) के एक दशक पूरे होने पर इसकी परिवर्तनकारी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने देश में तेज, सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल लेन-देन को नई गति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने यूपीआई उपयोग के अनुभव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से यह भी बताने को कहा कि यूपीआई ने उनके दैनिक जीवन को किस प्रकार सरल, सुविधाजनक और सहज बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले शुरू हुआ एकीकृत भुगतान अंतरफलक भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ है। इसने डिजिटल लेन-देन को सरल, तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हुए देश में भुगतान के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव किया है।

पिछले दस वर्षों में यूपीआई की पहुंच देश के कोने-कोने तक हुई है। इसके चलते डिजिटल भुगतान आम नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। छोटे दुकानदारों से लेकर उपभोक्ताओं और कारोबारियों तक, बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा के लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की व्यापक पहुंच और इसके लगातार विस्तार को भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की इस उल्लेखनीय और गौरवपूर्ण यात्रा पर हर भारतीय गर्व कर सकता है।

सीएम योगी का जेन-जी कनेक्शन, नियुक्ति पत्र बांटने के बाद युवाओं के साथ ली सेल्फी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद युवाओं के साथ सेल्फी लीं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपना संबोधन पूरा करने के बाद, सीएम योगी ने वहां मौजूद युवाओं से बातचीत की और उनके अनुरोध पर सेल्फी के लिए पोज़ दिया। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार अगले छह महीनों में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य भर के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगले छह महीनों में—कृपया ध्यान दें, अगले छह महीनों में—हम 1,00,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे,

जिन्हें हर हफ़्ते अलग-अलग बैच में बांटा जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश में 9,30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं और दावा किया कि इस दौरान किसी भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया की आलोचना करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलंदाज़ी से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन से ही 2017 से पहले के उस पैटर्न को तोड़ने का संकल्प लिया था, जिसमें भर्ती के विज्ञापन तो निकलते थे, लेकिन 'चाचा-भतीजे की जोड़ी' और पूरा 'महाभारत-शैली का कुनबा' वसूली के लिए पूरे राज्य में फैल जाता था।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवाओं का चयन बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बिना भेदभाव के सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो पूरे राज्य को इसका फ़ायदा मिलता है। राज्य उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है—और यह 'डबल-इंजन' वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की पिछले नौ से साढ़े नौ वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि सरकार अपराध के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपना रही है और धोखाधड़ी व गड़बड़ी में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि

भारतीय कंपनियां बनाएंगी पारंपरिक मिसाइलें : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इससे देश में इन मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी उत्पादन किया जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना है।

तकनीक हस्तांतरण के बाद पात्र भारतीय कंपनियां पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की डीआरडीओ-विकसित तकनीकों का देश में उत्पादन कर सकेंगी। इसके लिए संबंधित योग्यताओं, प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने और रक्षा विनिर्माण में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूती मिलेगी। यह पहल मिसाइल प्रणालियों के विकास से औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की ओर सफलतापूर्वक बदलाव को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण में भारतीय उद्योग की क्षमताओं का प्रभावी इस्तेमाल करना है।

पैनल को काम करने दें...अमित शाह की भूमिका की जांच वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई के विरोध-प्रदर्शन के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को अपनी जांच जारी रखने दी जानी चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के पुनर्गठन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सरकार और पुलिस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका की व्यापक जांच की मांग की थी। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस अर्ज़ी को जल्द लिस्ट करने की मांग की, जिसमें कमेटी के पुनर्गठन की अपील की गई थी। CJI ने कहा कि अर्ज़ी को लिस्ट किया जाएगा। सीजेआई ने कहा जो भी काम करेगा, वह इस कोर्ट की सीधी निगरानी में काम करेगा। हमने इस मामले का निपटारा नहीं किया है और हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कमेटी को अपना काम शुरू करने दें और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी कोई भी चिंता कोर्ट के सामने रखें। सीजेआई ने आगे कहा कि कभी-कभी हमें कुछ सीमाओं, जैसे उपलब्धता और अन्य कारकों के दायरे में भी काम करना पड़ता है। आप सभी भी समिति की मदद के लिए मौजूद हैं और जब भी कोई चिंता हो, तो हमें बता सकते हैं।

ऊना में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, 40 से अधिक घायल

ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के समीप मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार 40 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे।

सभी श्रद्धालु हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, श्रद्धालु दो दिन पहले पीर निगाह मंदिर में दर्शन करने और भंडारा आयोजित करने के लिए पहुंचे थे। मंगलवार सुबह वे पीर निगाह से माता नैना देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा।

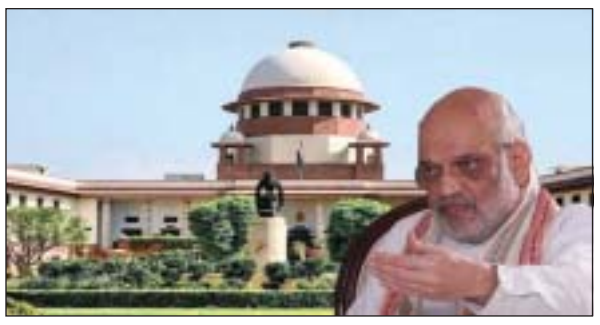

तरुण तेजपाल केस में बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर का दिया आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में अपनी सज़ा और 10 साल की जेल की सज़ा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होने तक सरेंडर करने से छूट मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें दो हफ़्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। जस्टिस आलोक अराधे ने तेजपाल की सरेंडर से छूट की अर्ज़ी खारिज कर दी और उन्हें सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर सर्टिफिकेट 22 सितंबर या उससे पहले जमा किया जाता है, तो उनकी अपील उसी तारीख को लिस्ट की जाए। तेजपाल की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमन लेखी ने दलील दी कि क्रिमिनल

अपील लिस्ट होने से पहले आरोपी का सरेंडर करना कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है। सिब्बल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 अगस्त के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया गया था। कोर्ट ने माना था कि मामला 13 साल पुराना है और वह अब एक सीनियर सिटिजन हैं जिनकी समाज में मज़बूत जड़ें हैं। सिब्बल ने कहा ऐसी कोई कानूनी शर्त नहीं है कि अपील लिस्ट होने से पहले उन्हें सरेंडर करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले तेजपाल को कुछ दिनों के लिए जेल भेजने का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने कहा उन्हें पांच दिन के लिए जेल भेजने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, बेंच ने साफ़ किया कि अपराध की प्रकृति और उन्हें सुनाई गई सज़ा की जांच किए बिना तेजपाल की छूट की अर्ज़ी पर फ़ैसला नहीं किया जा सकता।

जाति जनगणना को लेकर खड़गे-राहुल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बिहार, तेलंगाना मॉडल अपनाने की मांग की

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा ओपन-एंडेड प्रश्नावली (जिसमें कोई तय विकल्प नहीं होते) की जगह एक ऐसी प्रश्नावली का इस्तेमाल किया जाए जो सत्यापित जाति सूची पर आधारित हो, जैसा कि बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल में किया गया था।

खड़गे ने 'X' पर एक पोस्ट में तर्क दिया कि ओपन-एंडेड सवालों से जातियों की सटीक गिनती नहीं हो पाएगी और इससे एक ही जाति को अलग-अलग नामों और उप-जातियों के तहत दर्ज किए जाने का जोखिम

रहेगा। खड़गे ने लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक संयुक्त पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। खुले सवालों के ज़रिए जातियों की सही गिनती करना संभव नहीं है। अगर एक ही जाति को अलग-अलग नामों और उप-जातियों के तहत दर्ज किया जाता है, तो डेटा बिखरा हुआ होगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान OBC, सबसे पिछड़े और वंचित समुदायों को होगा।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग साफ है – मौजूदा प्रश्नावली (questionnaire) को रद्द किया जाए, जातियों की सत्यापित सूची के आधार पर एक नई प्रश्नावली तैयार की जाए, और राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों तथा जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों की तरह, पहले से तैयार और सत्यापित जाति सूची के आधार पर गिनती करना एक व्यावहारिक समाधान है। जाति जनगणना न केवल होनी चाहिए, बल्कि इसे सही तरीके से भी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और तेलंगाना के तरीके को अपनाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि बिहार के जाति सर्वेक्षण के नतीजे 2 अक्टूबर, 2023 को और तेलंगाना के नतीजे 4 फरवरी, 2025 को जारी किए गए थे। रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में जाति सर्वेक्षण के नतीजे 2 अक्टूबर, 2023 को और तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण के नतीजे 4 फरवरी, 2025 को जारी किए गए थे।

संक्षेप

बलात्कार के दोषी राम रहीम को 21 दिन की फरलो, 2 महीने बाद फिर बाहर आया

रोहतक। बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार की मेहरबानी से 2 महीने बाद फिर जेल से बाहर आने का मौका मिला। गुरमीत को 21 दिन की फरलो मिली। वह मंगलवार सुबह 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और 8 गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले, गुरमीत को 26 मई को 30 दिन की पैरोल मिली थी। गुरमीत को इस साल जनवरी में 40 दिन और मई में 30 दिन की पैरोल मिली थी। वह 25 जून को जेल लौटा। अब उसका पैरोल का कोटा खत्म हो गया है। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत जनवरी-दिसंबर तक कैदी 10 हफ्ते की पैरोल 2 हफ्ते में ले सकता है। गुरमीत इस साल 3 हफ्तों की फरलो का फायदा ले सकता है। फरलो को टुकड़ों में नहीं ले सकते और यह कभी भी ले सकते हैं। जनवरी में गुरमीत ने अपनी मां की बीमारी बताकर 40 दिन की पैरोल ली थी। इस दौरान वह बरनावा आश्रम उत्तर प्रदेश और फिर बागपत आश्रम में रहा। वर्ष 2017 में सजा के बाद उसे सबसे पहले अक्टूबर 2020 में एक दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद, फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो मिली। पिछले 9 साल में यह 17वीं बार जेल से बाहर आया है। वह 430 दिन से अधिक बाहर रहा है। राम रहीम को सिरसा स्थित आश्रम में महिला शिष्याओं के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा मिली है। पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अगस्त, 2017 में उसे दोषी ठहराया था। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में उसे उम्रकैद हुई है। पत्रकार को 2002 में गोली मारी गई थी। मार्च में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार हत्या मामले में गुरमीत को बरी कर दिया है।

बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे में 'बंदरबांट': सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- मंदिर की तिजोरी में पहुंचे एक-एक पैसा

नई दिल्ली, एजेंसी। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और धनराशि के गलत तरीके से निकाले जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया एक-एक पैसा या तो मंदिर की दानपेटियों में पहुंचे या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो। अदालत ने कहा कि चढ़ावे की राशि को किसी भी तरह से इधर-उधर किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थिति रिपोर्ट रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में बेहद गंभीर स्थिति सामने आई है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अदालत के समक्ष तस्वीरें और एक वीडियो भी पेश किया। सिंह ने बताया कि वीडियो में तीन लोग 'गोलक' यानी पारंपरिक दानपेटी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें अपनी पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर संतों की बैठक में हंगामा, रामनगरी में आंदोलन का एलान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावे के कथित विवाद को लेकर संत समाज की बैठक में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया, जब बैठक स्थल पर अयोध्या पुलिस और इंटेलिजेंस के जवान पहुंच गए। संतों ने आरोप लगाया कि उन्हें राम मंदिर चढ़ावे के कथित विवाद पर बैठक और चर्चा करने से रोका गया। बैठक स्थल से मीडिया कर्मियों को बाहर किए जाने को लेकर भी संतों और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति बनी। पुलिस और एलआईयू की तैनाती से संतों में नाराजगी और बढ़ गई।कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संतों ने राम मंदिर चढ़ावे के कथित घोटाले की उच्चस्तरीय जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग उठाई। संतों ने चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संतों का आरोप है कि एसआईटी की जांच में छोटे आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जबकि बड़े लोगों को बचा लिया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

एक लाख संतों के साथ आंदोलन का एलान

बैठक के बाद कंप्यूटर बाबा ने कहा कि संत समाज चढ़ावे के कथित विवाद की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो एक लाख संतों के साथ अयोध्या पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। संत समाज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी कर रहा है। संतों ने कहा कि वे रामलला का दर्शन कर चढ़ावे के कथित विवाद को लेकर भगवान श्रीराम से क्षमा मांगेंगे। संतों ने आरोप लगाया कि अयोध्या में चढ़ावे के विवाद पर बोलने से उन्हें रोका जा रहा है।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

बैठक के दौरान पुलिस और एलआईयू की मौजूदगी को लेकर भी संतों ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि संत समाज की बैठक में पुलिस की इस तरह मौजूदगी उचित नहीं है। बैठक में शामिल संतों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई।

नौकरी के साथ और नौकरी के बाद मां–बहन–बेटियों की कीमत लगाने वाला खुलेआम घूम रहा है

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जुबान का गंदा एक सांस में किसी की भी मां-बहन और बेटी की कीमत लगा देने का दम-खम रखने वाला सेवानिवृत्त वन रक्षक नरेंद्र बहादुर सिंह पर अबतक कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है,लेकिन आजतक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण इतना मनबढ़ हो चुका है की सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी ही नही जाति विशेष को संबोधित करते हुए मां बहन बेटी की गाली-गलौज करता रहा है पर एफआईआर तो दर्ज हो जाती है परंतु कार्रवाई कभी भी नही हुई,बल्कि वन रक्षक की नौकरी करते समय नरेंद्र बहादुर सिंह ने ऐसी ही बेहूदा हरकत की थी जिसका ऑडियो वायरल हुआ था,उसके बाद उसे दूसरे रेंज से सम्बद्ध किया गया था,सूत्रों की माने तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार विभागीय कार्यों में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करना जारी रखा है,उसके इसी अवैधानिक कार्यों पर जो भी वन विभाग का कर्मचारी या अधिकारी रोक लगाने का प्रयास करता है उसे उसका खामियाजा अपनी मां-बहन और बेटी के लिए घिनौने शब्दों की सार्वजनिक रूप से कीमत चुकानी पड़ती है,अभी हाल में पूर्व वन रक्षक नरेंद्र बहादुर सिंह के दो ऑडियो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हुए,जिसमें एक डिप्टी रेंजर और एक वन दारोगा की मॉ बहन और बेटी की कीमत लगाते हुए जाति विशेष की गालियां दे रहा है।

महाकाल के पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक से भक्तों में उमंग, शिवभक्ति से गूंजा क्षेत्र

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूरे माह बल्दीराय तहसील क्षेत्र सहित गांवों और कस्बों के शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि, शांति तथा लोककल्याण की कामना की। सावन की हर सुबह शिवालयों में घंटियों की गूंज और हर सोमवार भक्तों की लंबी कतारें शिवभक्ति की गहरी आस्था का प्रमाण बनी रहीं। पूरे वर्ष में सावन महीना, तीर्थवर्ष के रुप में जनकल्याण का माना जाता है। लोगों की आस्था, भक्ति, भगवान शिव जी के प्रति समर्पित हो जाती है ।

सनातन परंपरा में भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव, कल्याणकारी और करुणामय देवता माना गया है। वे सृष्टि के संहारक होने के साथ ही लोकमंगल के प्रतीक भी हैं। वैदिक परंपरा के श्री रुद्रम में भगवान रुद्र को नमन करते हुए कहा गया है नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थात शिव को और भी अधिक कल्याणकारी स्वरूप को नमन। यही भावना शिव आराधना को लोककल्याण से जोड़ती है। पुराणों में समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव द्वारा अपने कंठ में धारण करने का प्रसंग उनके त्याग और जगत की रक्षा के भाव को दर्शाता है। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। शिवपुराण की परंपरा में शिवलिंग की पूजा और अभिषेक को श्रद्धा एवं आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। रामचरितमानस में भी भगवान श्रीराम और शिव के संबंध को अत्यंत श्रद्धापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं।

सपा के बैनर तले गजापुर में हुआ पीडीए सम्मेलन

सुल्तानपुर। लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गजापुर में पीडीए जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के आयोजक जयश्री प्रसाद पाल एवं सह आयोजक शिव प्रसाद गौतम व गयादीन पाल संयुक्त रूप से रहे। सम्मेलन में पीडीए समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक जागरूकता का संदेश दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी से लम्भुआ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शिक्षक श्यामलाल निषाद षाुरूजीष् ने कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि जिन मासूम बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं जो बेहद चिंता का विषय है। सम्मेलन के संयोजक उदयभान विश्वकर्मा तथा सह संयोजक बजरंगी पाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय मौर्य ने की, जबकि महेंद्र यादव एवं सुभाष चन्द्र मौर्य के संयुक्त संरक्षण में सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

जीवनसंगनी ने निभाया सात फेरों का वचन : मां ने मना किया, पति ने रोका फिर भी सुहाग के लिए डोनर बनी पत्नी, ऐसे बचाई जान

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। जिंदगी गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं है, पति को खिलौना समझ कर ना बदलें। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, सुख-दुख आते-जाते रहते हैं, अपने हमसफर का अंतिम सांस तक साथ दें। आए दिन पति की हत्या, पति पत्नी के बीच विवाद की घटनाएं सामने आने पर एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पहले गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए पति को गुर्दा दान करने वाली पत्नी मीना ने महिलाओं के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्हें सीख दी है कि वैवाहिक जीवन के हर संघर्ष में पति व पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए।

एसएन की सुपरस्पेशियलिटी विंग में शनिवार को सिकंदराराऊ, हाथरस के रहने वाले 32 वर्ष के महेंद्र को उनकी पत्नी 30 वर्ष की मीना का गुर्दा प्रत्यारोपित किया गया है। मरीज किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में भर्ती हैं और उनकी पत्नी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रेवाड़ी एटा की रहने वाली मीना ने बताया कि 2015 में शादी हुई थी। वो (महेंद्र) गुडगांव में कंपनी में काम करते थे।

दो वर्ष पहले गुर्दा रोग का पता चला, जयपुर में इलाज कराया। इसके बाद एसएन में नेफ्रोलाजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अपूर्व जैन से इलाज शुरू कराया। उन्हें हर सप्ताह दो से तीन दिन डायलिसिस के लिए लेकर आती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए परचून की दुकान खोल ली।

कौन देगा गुर्दा तो सभी ने कर दिया था मना

डॉक्टर ने गुर्दा प्रत्यारोपण कराने के लिए, पूछा कौन गुर्दा देगा। मेरे हां करने पर, मेरी मां ने भी गुर्दा देने से मना किया, उन्होंने भी कहा कि मेरी तबीयत खराब है गुर्दा दे दिया तो 10 वर्ष की बेटी और दो बेटों की परवरिश कैसे होगी लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। धीरे-धीरे हालात बदले, डॉक्टर ने भी काउंसलिंग की। समझाया कि दो गुर्दे होते हैं एक गुर्दे से भी काम चल जाता है। इसके बाद सब तैयार हो गए।

वीडियो कॉल से की बात, पूछा ठीक हो

किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में भर्ती महेंद्र से मीना की वाट्सएप वीडियो कॉल पर बात कराई गई। दोनों भावुक हो गए, पूछा ठीक हो। मीना ने असाध्य रोग निधि से निश्शुल्क गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही एसएन के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता और डॉक्टर्स की टीम का आभार व्यक्त किया।

गोरखपुर में बैंककर्मी के घर में चोरी करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। बैंककर्मी के बंद मकान में का ताला तोड़कर जेवर और नकदी चोरी करने वाले बदमाश को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने सोमवार देर रात लहसड़ी अंडरपास के पास मुठभेड़ में दबोच लिया। तुर्कमानपुर नई मस्जिद निवासी मो. शहजादे के बाएं पैर में गोली लगी है।

पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के जेवर, 10 हजार रुपये, मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया है। जिला अस्पताल में बदमाश का उपचार चल रहा है।

फुलवरिया निवासी इंद्रमोहन सिंह निजी बैंक में उपशाखा प्रबंधक हैं। पिता की मौत होने पर 20 अगस्त को वह परिवार के साथ पैतृक गांव गए थे। इसी दौरान बंद मकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने आलमारी में रखे जेवर और नकदी चोरी कर ली थी।वारदात सीसी कैमरे में कैद हुई थी। फुटेज में तीन बदमाश दिखाई दिए थे। जांच के दौरान पुलिस को तुर्कमानपुर निवासी शहजादे के बारे में जानकारी मिली।

सोमवार देर रात उसके लहसड़ी अंडरपास के पास होने की सूचना मिली। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक श्यामा नंद राय और एंटीथेफ्ट सेल प्रभारी निरीक्षक सुनील राय की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पुलिस टीम को देखते ही शहजादे ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। तलाशी में उसके पास से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस, चोरी के चार कंगन, एक अंगूठी, मंगलसूत्र, गले का हार और 10 हजार रुपये मिले हैं।

उसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ में शहजादे ने अपने साथी नियाज अहमद निवासी जमुनहिया बाग, थाना गोरखनाथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ चोरी करने की जानकारी दी है। पुलिस दोनों की तलाश में दबिश दे रही है। एसपी सिटी ने बताया कि बदमाश पर 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

मौजूदा विधायक का टिकट कटा तो प्रभाकर रिंकू शुक्ला पर लग सकता है दांव?

सुल्तानपुर। जयसिंहपुर सदर सीट पर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मौजूदा दावेदार राजबाबू का टिकट किसी वजह से कटता है, तो पार्टी का अगला भरोसा किस युवा चेहरे पर होगा? सियासी गलियारों में दो नामों की चर्चा तेज है प्रभाकर 'रिंकू' शुक्ला और प्रदीप मिश्रा 'सरकार'। लेकिन अगर बात करें सामाजिक पकड़, व्यक्तिगत जनसंपर्क और क्षेत्र में सक्रियता की तो फिलहाल रिंकू शुक्ला की दावेदारी मजबूत नजर आती है। क्योंकि रिंकू शुक्ला की सियासी पहचान सिर्फ टिकट की दावेदारी तक सीमित नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के एक बड़े उद्योगपति और सामाजिक संस्था लोकाधिकार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सामाजिक सरोकार और लोगों के सुख-दुख में खड़े रहने की छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। जरूरतमंदों की मदद हो या किसी परिवार की परेशानी हो या फिर सामाजिक सरोकार का कोई मुद्दा तो रिंकू शुक्ला की सक्रियता उन्हें आम लोगों से जोड़ती है।

कानपुर में कचरे के ढेर में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफी, लूटने की मची होड़

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर के पनकी में हाईवे किनारे पड़ी एक्सपायरी टॉफी और चॉकलेट लूटने की होड़ मच गई। जिसका वीडियो सोमवार देर रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि ये वीडियो कब का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि वीडियो एलएमएल चौराहे से थम्सअप चौराहे के बीच में स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पीछे हाईवे का है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए किसी चॉकलेट कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफी के डिब्बे फेंके गए हैं।

जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को हुई, लोग टॉफी और चॉकलेट बटोरने पहुंच गए। किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है।

हालांकि जांच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि वीडियो कब का है और किस फैक्ट्री द्वारा टॉफी और चॉकलेट फेंकी गई है। जिस तरह से कंपनी ने एक्सपायर टॉफी और चॉकलेट हाईवे किनारे फेंक दिए हैं वो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

जांच में पुलिस को एक्सपायर टॉफियों के कुछ खाली,मिट्टी से सने व फटे हुए रैपर मिले हैं। जिसमें एन और गुजरात लिखा हुआ दिखाई दिया है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

थाना प्रभारी दिनेश विष्ट ने बताया कि रात्रि एक बजे प्रचलित वीडियो सामने आया है। संबंधित विभाग को सूचना दी गई है और जांच कराई जा रही है। वीडियो कुछ दिन पुराना हो सकता है।मिट्टी से सने रैपर में गुजरात लिखा हुआ मिला है।

यूपी चुनाव से पहले लगेगा बड़ा झटका!: रालोद में बड़ी टूट की आहट, इस बात से नाराज बड़े नेता छोड़ सकते हैं साथ

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सहारनपुर जिले की राजनीति में दल बदल की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। तीन सितंबर को रालोद मुखिया जयंत चौधरी रामपुर मनिहारान में जनसभा करेंगे। इससे पहले रालोद में बड़ी टूट की आहट सुनाई देने लगी है।

पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी जल्द ही किसी दूसरे राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी में लगातार उपेक्षा और सम्मान न मिलने से पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। रालोद के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है।

राजनीतिक दिग्गजों की मानें तो इन पदाधिकारी को पिछले कुछ समय से पार्टी के कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में भी महत्व नहीं मिल रहा है। पदाधिकारी दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि अभी तक उनके संभावित नए दल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

राजनीतिक गलियारों में लगातार जारी हैं अटकलें

समर्थकों का कहना है कि चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और कई नेता अपनी भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए नए विकल्प तलाश रहे हैं। उनके पार्टी छोड़ने की चर्चाओं पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अटकलें लगातार जारी हैं।

जिले में हाल के दिनों में दल बदल की राजनीति भी चर्चा में रही है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री शायान मसूद ने भी सपा का दामन थामा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें, कि तीन सितंबर को रालोद मुखिया जयंत चौधरी की रामपुर मनिहारान में जनसभा है, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही है।

रालोद के गिर चुके हैं कई विकेट

रालोद में पिछले कुछ माह से एक के बाद एक बड़े पदाधिकारी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। प्रदेश स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व एमएलसी डॉ. रामाशीष राय ने भी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया है। इसके अलावा अन्य जिलों के कई बड़े पदाधिकारी भी छोड़कर जा चुके हैं।

सहारनपुर की बात करें तो यहां पर पूर्व जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम ने कुछ माह पहले रालोद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आसपा का दामन थाम लिया था, तभी से वह आसपा में पूरी तरह सक्रिय है। जिले में यह दूसरा बड़ा झटका हो सकता है।

ऐतिहासिक होगी रालोद की स्वाभिमान रैली : चंदन

सहारनपुर सर्किट हाउस सभागार में रालोद की बैठक में आगामी तीन सितंबर को होने वाली स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। सांसद एवं रालोद महासचिव चंदन चौहान ने कहा कि रामपुर मनिहारान के गोचर महाविद्यालय में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी।

केंद्र में मंत्री बनने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का सहारनपुर में यह पहला कार्यक्रम होगा। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शाहजमां खान और संचालन प्रदेश सचिव चौधरी धीर सिंह ने किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, चौधरी अय्यूब हसन, भूषण चौहान, रमेश चौहान, महावीर सैनी, शिवकुमार गुर्जर, शमीम अहमद, फैसल त्यागी मौजूद रहे।

वहीं रामपुर मनिहारान में रालोद की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को राष्ट्रीय महासचिव एवं बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने गोचर कृषि इंटर कॉलेज में पहुंचकर संस्थान के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों की रूपरेखा तय की।

कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह, गोचर कृषि इंटर कॉलेज के प्रबंधक अमित चौधरी आदि पदाधिकारियों ने स्वाभिमान सभा को सफल बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया।

चीनी की महंगाई से फीकी पड़ने लगी राखी की मिठास, चाय की चुस्की पर भी बढ़ा बोझ

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही तहसील क्षेत्र के कई बाजारों में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। महंगी चीनी का सीधा असर घरेलू बजट के साथ-साथ त्योहार की तैयारियों पर भी पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कीमतों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो इस बार राखी की मिठास महंगाई की चाशनी में फीकी पड़ सकती है। क्षेत्रीय बाजार धनपतगंज, हरौरा बाजार, देहली बाजार, बहुरावां बाजार, भवानीगढ़, हलियापुर, तिरहूँत बाजार, पारा बाजार, बल्दीराय बाजार, वलीपुर, लँगड़ी बाजार, सुरेशनगर आदि बाजार क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बीच चीनी की कीमतों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। चाय से लेकर घर में बनने वाली मिठाइयों और पकवानों तक चीनी की बढ़ती कीमत का असर साफ दिखाई दे रहा है। त्योहार के मौसम में मांग बढ़ने के बीच कीमतों में उछाल ने आम परिवारों की चिंता और बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार की ओर से चीनी का पर्याप्त भंडारण और बाजार में उपलब्धता का दावा किया जाता है, तो तहसील क्षेत्र के बाजारों में उपभोक्ताओं को महंगी चीनी क्यों खरीदनी पड़ रही है? क्या जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा आपूर्ति व्यवस्था में किसी स्तर पर गड़बड़ी इसकी वजह है? इन सवालों का जवाब जिम्मेदार विभाग को देना चाहिए। उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से तत्काल बाजारों की जांच कराने, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के स्टॉक का सत्यापन करने तथा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

यूपी में चीनी की कमी नहीं, 28 लाख टन का स्टॉक: सीएम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। देश में चीनी की कीमतों में अचानक आए भारी उछाल को लेकर लोगों में घबराहट है। वहीं सरकार का भी कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, अगले कुछ दिनों में कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश में चीनी की उपलब्धता को लेकर कहा कि यहां पर चीनी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 28 लाख टन चीनी मौजूद है। लखनऊ में 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में चीनी की संकट की चर्चा की चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है।

15 अक्टूबर से फिर से चलेंगे चीनी मिल : CM योगी

उन्होंने कहा, "यूपी की एक महीने की कुल खपत 4 लाख टन चीनी है। हमारे पास कुल 28 लाख टन मौजूद है। ऐसे में हमारे पास करीब 7 महीने की चीनी का स्टॉक मौजूद है, और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करने जा रहे हैं, तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है।" सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ प्रदेश की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है।

यूपी दूसरे राज्यों को भी दे सकता है चीनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूरे देश को चीनी उपलब्ध करा सकता है . प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना और चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल है . ऐसे में यहां उत्पादन और स्टॉक की स्थिति का असर राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ता है . सरकार के मुताबिक मौजूदा 28 लाख टन स्टॉक, करीब सात महीने की उपलब्धता और आगे प्रस्तावित 90 लाख टन उत्पादन को देखते हुए यूपी में चीनी संकट की स्थिति नहीं है .

पारदर्शिता के साथ नियुक्ति चुनौती : CM योगी

नियुक्ति को लेकर सीएम योगी ने कहा, "आज के दिनों में पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र दिया जाए यह एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन हमारे आयोग और बोर्ड इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जब हम योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे राज्य को मिलता है, उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ पूरा राज्य लेता हुआ दिखाई देता है और यही तो पिछले कुछ सालों में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार की उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है।"

6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी : CM योगी

पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं प्रदेश भर के सभी युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, "आप इस बात को नोट कर लीजिए अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग-अलग स्टेज में हर हफ्ते उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को 9 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दिलाने की सफलता प्राप्त हुई। जबकि 2017 से पहले, चाचा-भतीजे की जोड़ी और पूरा खानदान वसूली के लिए निकलता था प्रदेश में। समय और उम्र हमारे युवाओं की खराब होती थी।

महंगी चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति पर त्वरित निर्णय की मांग, अजय राय ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने महंगी होती चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति की वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और उपभोक्ता हितों के दृष्टिकोण से स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को एथेनॉल, चीनी उत्पादन, घरेलू कीमतों और चीनी के आयात के बीच वास्तविक संबंधों का पूरा लेखा-जोखा देश की जनता के सामने रखना चाहिए।अजय राय ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि उन्होंने गत 7 जुलाई को एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति से जुड़े विभिन्न सवालों को लेकर विस्तृत पत्र भेजा था। उसमें ई-20, ई-85 और ई-100 ईंधन की नीति की स्वतंत्र समीक्षा करने, इसके आर्थिक प्रभावों का आकलन करने तथाउपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की कथित रूप से अनदेखी के लिए केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिमंडल से हटाने का आग्रह भी किया था।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति का सरकार की ओर से प्रमुख तर्क यह दिया जाता रहा है कि इससे पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

संक्षेप

प्रवर्तन कार्य में लापरवाही पर 10 यात्री-मालकर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई

लखनऊ। परिवहन विभाग में प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बेहद कम कार्रवाई करने वाले 10 यात्री-मालकर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास यानी अप्रैल से जून 2026 तक की प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की।समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ यात्री-मालकर अधिकारियों ने अप्रैल से जून 2026 के बीच प्रशमन शुल्क वसूली के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बेहद कम कार्रवाई की। परिवहन आयुक्त ने इसे विभागीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता माना है।परिवहन आयुक्त ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में इस प्रकार की लापरवाही और उदासीनता शासन एवं विभाग की मंशा के विपरीत है। इससे विभागीय राजस्व की पूर्ति भी प्रभावित होती है।प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त ने निर्धारित प्रशमन शुल्क लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत न्यून कार्रवाई करने वाले 10 यात्री-मालकर अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की है।

शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाने और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। वजीरगंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और शादी के लिए कहने पर गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार दोपहर रिवरबैंक कॉलोनी कट के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2026 को वादिनी की ओर से थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि नामजद व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वादिनी ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो उसने उसके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी।तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या 217/2026 धारा 69 और 352 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की।पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की।

काकोरी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम करीमाबाद में मंगलवार सुबह उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से करीब 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही काकोरी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान कामिल पुत्र रमजान, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम शरुआ, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के रूप में हुई है। कामिल अपनी बहन के घर ग्राम करीमाबाद, थाना काकोरी आया हुआ था और वहीं रह रहा था।बताया गया कि मंगलवार सुबह करीब नौ बजे कामिल घर की छत पर मौजूद था। इसी दौरान वह छत के पास से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। विद्युत करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना काकोरी पुलिस पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना से संबंधित जानकारी जुटाई।

उत्तर प्रदेश में 16,478 परियोजनाओं में 12 .10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आगे बढ़ा, हर जिले में तय होगा वार्षिक निवेश लक्ष्य : नन्दी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर में तेजी से बदलाव और निवेशकों के बढ़ते विश्वास के बीच मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंथन एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने बैठक में इन्वेस्ट यूपी, उद्यमी मित्रों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा उद्योगों के विकास तथा निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल समझौता ज्ञापन करना नहीं, बल्कि निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।मंत्री नन्दी ने कहा कि स्पष्ट नीति, ईमानदार नीयत और परिणाम देने वाली व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से उभर रहा है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रदेश का योगदान लगभग 9.1 प्रतिशत है।उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आने वाले समय में इसे 39.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच रहा है।मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 33,068 पंजीकृत कारखाने लगभग 38.09 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें 2.09 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ता निवेश युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार तथा परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन रहा है।नन्दी ने कहा कि अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों के माध्यम से 16,478 परियोजनाओं में 12 लाख 10 हजार 274 करोड़ रुपये के निवेश को क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह-5.0 की तैयारियां भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों की समस्याओं के समाधान, आवश्यक अनुमोदन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निवेश के बाद भी सहयोग उपलब्ध कराने में इन्वेस्ट यूपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश का औद्योगिक विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक जनपद की स्थानीय क्षमता और संभावनाओं के आधार पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, कहीं वस्त्र एवं लॉजिस्टिक्स, तो कहीं सेवा क्षेत्र और नई तकनीक आधारित उद्योग स्थापित हो रहे हैं।

'डिग्री अवसर का द्वार खोलती है, कौशल सफलता में बदलता है'

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा में आयोजित दीक्षारम्भ समारोह में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ कौशल, नवाचार तथा उद्यमशीलता पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया।समारोह को संबोधित करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जीवन में सफलता सबसे पहले व्यक्ति के मन और सोच से शुरू होती है। 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' केवल कहावत नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। यदि विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं तो परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, सफलता हासिल की जा सकती है।उन्होंने कहा कि कक्षा 12 के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश विद्यार्थियों के जीवन में एक नए सफर की शुरुआत है। आने वाले तीन-चार वर्ष उनके जीवन के बेहद महत्वपूर्ण वर्ष हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नई चीजें सीखने, प्रयोग करने, अपनी रुचियों को पहचानने और नए कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।मंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उनके माता-पिता ने उनके भविष्य को लेकर बड़े सपने देखे हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों का दायित्व है कि वे अपने माता-पिता के सपनों को संकल्प, अनुशासन और परिश्रम के माध्यम से साकार करें।उन्होंने कहा कि वर्तमान समय केवल डिग्री हासिल करने का नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और नवाचार का समय है।

महंगी चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति पर त्वरित निर्णय की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने महंगी होती चीनी और एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति की वैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और उपभोक्ता हितों के दृष्टिकोण से स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को एथेनॉल, चीनी उत्पादन, घरेलू कीमतों और चीनी के आयात के बीच वास्तविक संबंधों का पूरा लेखा-जोखा देश की जनता के सामने रखना चाहिए।अजय राय ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि उन्होंने गत 7 जुलाई को एथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति से जुड़े विभिन्न सवालों को लेकर विस्तृत पत्र भेजा था। उसमें ई-20, ई-85 और ई-100 ईंधन की नीति की स्वतंत्र समीक्षा करने, इसके आर्थिक प्रभावों का आकलन करने तथाउपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की कथित रूप से अनदेखी के लिए केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिमंडल से हटाने का आग्रह भी किया था।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति का सरकार की ओर से प्रमुख तर्क यह दिया जाता रहा है कि इससे पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 19.24 प्रतिशत तक पहुंच गया था और 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में नीति आगे बढ़ रही थी। अजय राय ने सवाल उठाया कि जब एथेनॉल मिश्रण लगातार बढ़ाया जा रहा है।

यूपीआई के 10 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे होना डिजिटल भारत की बड़ी उपलब्धि : केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के 10 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल, सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी बनाकर सुशासन तथा वित्तीय समावेशन को नई गति प्रदान की है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीआई ने डिजिटल लेन-देन को आम नागरिक के जीवन का सहज हिस्सा बना दिया है। इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की पहुंच समाज के व्यापक वर्ग तक सुनिश्चित हुई है।उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों, किसानों और श्रमिकों से लेकर छोटे-बड़े व्यापारियों तथा उद्यमियों तक पहुंचा है। यूपीआई के माध्यम से सभी वर्गों को सुगम और त्वरित भुगतान की सुविधा मिल रही है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ आमजन के आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभिनव पहल के रूप में शुरू हुआ यूपीआई आज आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल शक्ति और वैश्विक पटल पर भारत की तकनीकी क्षमता का सशक्त प्रतीक बन चुका है। करोड़ों नागरिकों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह त्वरित, सुगम और विश्वसनीय भुगतान का माध्यम बन गया है।उन्होंने कहा कि यूपीआई की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होना 'डिजिटल इंडिया' से 'आत्मनिर्भर भारत' तक की विकास यात्रा में देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता, नवाचार और संकल्प की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ . मृदुल त्रिपाठी प्रतिष्ठित ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी ट्रैवल ग्रांट के लिए चयनित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ. मृदुल त्रिपाठी (जूनियर रेज़िडेंट -तृतीय वर्ष) को ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी (बी.टी.एस) ट्रैवल ग्रांट के लिए चयनित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 9वीं वार्षिक पैक्स 2026 अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में प्राप्त हुआ है। सांस के रोगों पर आधारित यह अंतराष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ है। पैक्स श्वसन रोगों के क्षेत्र में देश-विदेश के विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित वार्षिक सम्मेलन है, इसमें पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, एलर्जी, अस्थमा, टीबी, स्लीप मेडिसिन और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी जैसे विषयों पर नवीनतम शोध, दिशा-निर्देश और तकनीकी प्रगति साझा की जाती है। यह मंच युवा चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को अपने कार्य को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने और विशेषज्ञों से संवाद का अवसर प्रदान करता है। पैक्स 2026 में देश-विदेश से आये सैकड़ों शोध-पत्रों में से पाँच सर्वोच्च पुरस्कार अत्यंत प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी (बी.टी.एस) ट्रैवल ग्रांट प्रदान किया जाता है। ट्रैवल ग्रांट एक वित्तीय सहायता है, जो शोधकर्ता या छात्र को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने और अपना शोध प्रस्तुत करने हेतु प्रदान की जाती है। इसमें ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पंजीकरण, यात्रा तथा रहने आदि के लिए अनुदान पैक्स फाउंडेशन द्वारा डॉ. मृदुल त्रिपाठी को प्रदान किया जायेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नवम्बर 2027 में लंदन यूके में प्रस्तावित है।

डॉ. मृदुल त्रिपाठी को यह उपलब्धि उनके शोध प्रस्तुतीकरण "हाइपरकैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ भर्ती मरीजों में नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के फेल होने के लिए जिम्मेदार कारणों पर शोध" विषय पर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान की गई। यह अध्ययन गंभीर सांस रोगियों के उपचार में नये दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और गहन चिकित्सा के क्षेत्र में भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस उपलब्धि पर डॉ. मृदुल त्रिपाठी ने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि विभाग की सामूहिक मेहनत और टीमवर्क का प्रतीक है। उन्होंने विभागाध्यक्ष प्रो. सूर्यकान्त तथा विभाग के सभी चिकित्सा शिक्षको, सहकर्मी रेज़िडेंट्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का भी आभार व्यक्त किया। उनके सहयोग और समर्पण के बिना यह शोध संभव नहीं हो पाता।

इसी कान्फ्रेंस में विभाग के डॉ. तुषार सरीन ने पैक्स 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित ''स्मार्टर माइंड्स कॉम्पटीशन'' में ''नॉर्थ जोन में प्रथम स्थान'' प्राप्त कर 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि हासिल की। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने सम्मेलन में उनकी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही, डॉ. तुषार सरीन ''पोस्टर प्रेजेंटेशन'' में भी विन्नर रहें। उनके पोस्टर की गुणवत्ता एवं विषयवस्तु से प्रभावित होकर पैक्स 2026 के आयोजकों द्वारा उनके पोस्टर को ''पैक्स जर्नल में प्रकाशित करने का अवसर'' प्रदान किया गया है।

विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल डॉ. मृदुल त्रिपाठी एवं डॉ. तुषार सरीन के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की शैक्षणिक उत्कृष्टता और रोगी देखभाल में निरंतर प्रगति का भी प्रतीक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने भी डॉ. मृदुल त्रिपाठी एवं डॉ. तुषार सरीन तथा विभाग को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है।

सरस्वती-सिंधु सभ्यता ने भारतीय ज्ञान परंपरा को दिए नए आयाम : डॉ . नरेंद्र परमार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ की ओर से आयोजित 'पुरातत्व अभिरुचि पाठ्यक्रम-2026' के छठवें दिन सरस्वती-सिंधु सभ्यता और प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। मुख्य वक्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर तथा चंडीगढ़ के संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉ. नरेंद्र परमार ने 'सरस्वती-सिंधु सभ्यता : भारतीय ज्ञान परंपरा के नए आयाम' तथा 'प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने विषय से जुड़े पुरातात्त्विक साक्ष्यों और ज्ञान-पद्धतियों का प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया।पुरातत्व विभाग की निदेशक रेनू द्विवेदी ने बताया कि डॉ. परमार ने भारत में ज्ञान परंपरा के प्राचीन विकासक्रम को पुरातात्त्विक साक्ष्यों के माध्यम से समझाते हुए सरस्वती-सिंधु सभ्यता को प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय समाज में विकसित ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण, तकनीक, उत्पादन, कृषि और सामाजिक जीवन के व्यावहारिक अनुभवों से भी गहराई से जुड़ा हुआ था।

व्याख्यान के दौरान सरस्वती-सिंधु सभ्यता के पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आधार पर नगरीय नियोजन, वास्तुकला, जल एवं पर्यावरण प्रबंधन, मापन एवं गणितीय ज्ञान, कृषि, शिल्प एवं प्रौद्योगिकी, धातुकर्म, सामुद्रिक एवं दूरवर्ती व्यापार तथा प्रकृति एवं जीव-जगत से संबंधित ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

'जेन जी ' के लिए डिप्रेशन बन गया

क्या बुद्धि का दिवालियापन है कि नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा की दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ देश के नौजवान सड़कों पर उतरे और आंदोलन किया तो भाजपा के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री नौजवानों की आपस में शॉर्ट मैसेजिंग की भाषा बोल कर उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं! ऐसा लग रहा है, जैसे देश का 'जेन जी' यानी 14 से 29 साल तक की उम्र का युवा इस वजह से नाराज था कि देश के नेता उनकी भाषा नहीं बोलते हैं और नहीं समझते हैं। असल में नौजवान यह नहीं चाहते हैं कि 76 साल के प्रधानमंत्री और 76 साल के सरसंघचालक अपनी बातचीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिन्हें 'जेन जी' की भाषा के तौर पर सोशल मीडिया में प्रचारित किया जाए। हालांकि यह भी महामूर्खतापूर्ण बात है कि शब्दों या वाक्यों के शॉर्ट फॉर्म में बोलना 'जेन जी' की पहचान है। पहले की पीढ़ियों की भी अपनी शब्दावली होती थी। पहले भी बातें शॉर्ट फॉर्म में कही जाती थीं और तब भी वह पीढ़ी यह नहीं चाहती थी कि नेता उसके साथ उस भाषा में संवाद करें।

अभी सरकार और विपक्ष दोनों के नेता 'जेन जी' के साथ कनेक्ट करने के लिए उसकी डिक्शनरी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इससे वे नौजवानों को पटा लेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। इसका कारण यह है कि नौजवान पीढ़ी को लेकर नेताओं की समझ बुनियादी रूप से गलत है। इस पीढ़ी ने हर घटना, घटनाक्रम और अपने जीवन से जुड़ी बातों के लिए अपने शब्द बनाए हैं। उनके शब्दों के मायने पारंपरिक अर्थ से बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरी बात यह है कि वे तुरंत सामने वाले व्यक्ति को बॉक्स्ड करते हैं। एक खांचे में डालते हैं और उसके बाद आप कुछ भी कहते रहे वे आपको इस खांचे से बाहर नहीं देखेंगे।

'जेन जी'के लिए पढ़ाई और नौकरी या रोजगार के अलावा जो चीजें सबसे अहम हैं, उनके प्रति अगर सरकार सरोकार नहीं दिखाती है तो वह उनका विश्वास नहीं जीत सकती है। चाहे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कितनी भी बात कर लें। उनका एक सरोकार पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बदलाव को लेकर है। तभी किसान आंदोलन के समय 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग उनकी नायक बन गई थी। उनका दूसरा सरोकार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है और तीसरा सरोकार अपनी पहचान को लेकर है। दुर्भाग्य से भारत की सरकार इनमें से किसी को भी एड्रेस नहीं कर रही है। पर्यावरण को लेकर हम गंभीर नहीं हैं। प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं है। ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य का पुरानी पीढ़ी के लोग मजाक ही उड़ाते हैं। कई लोग कहते मिल जाएंगे कि हमारे लिए जो मामूली स्ट्रेस था वह 'जेन जी' के लिए डिप्रेशन बन गया है। इससे आप उनको अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे। उलटे और दूर करेंगे। ऐसे ही पहचान का मामला है। वे एलजीबीटीक्यू का समर्थन करते हैं। याद करें कैसे युवाओं के आंदोलन में जंतर मंतर पर सबसे पहले एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग पहुंचे थे। तब राइटविंग का पूरा इकोसिस्टम उनका मजाक उड़ाता था। क्या उस पहचान को स्वीकार किए बगैर कोई भी पार्टी या नेता 'जेन जी' से जुड़ सकता है?

भारत ही नहीं पूरी दुनिया का राइटविंग उनकी इस पहचान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। याद करें कैसे सत्ता में आते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका में अब सिर्फ दो ही जेंडर होंगे। यानी थर्ड जेंडर के लिए कोई जगह नहीं होगी। भारत का राइटविंग भी इसी सोच का है। तभी यह तय मानें कि सिर्फ उनकी भाषा के शब्द बोलने से काम नहीं चलने वाला है। उनके विचारों को भी स्वीकार करना होगा। वे पहचान को लेकर जो विचार रखते हैं और संबंधों को लेकर जो विचार रखते हैं। वे जितनी सहजता से लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार कर रहे हैं क्या राइटविंग या उनसे पहली वाली पीढ़ी उतनी ही सहजता से उसे स्वीकार कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा।

सोचें, प्रधानमंत्री को अचानक याद आया कि सात अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उन्होंने युवाओं के साथ कनेक्ट होने के लिए 'जीआरडब्लुएम' यानी 'गेट रेडी विद मी' कहते हुए एक वीडियो बनाया और हस्तकरघा, बुनकर आदि को बचाने और भारत के पारंपरिक वस्त्रों को प्रमोट करने की बात कही। दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की पेट डॉग 'नूरी' को लेकर आए और उसके साथ वीडियो बनाई। पशु प्रेम और इथनिक चीजें भी युवाओं को पसंद आती हैं। लेकिन इस रूप में उनका प्रमोशन करके देश के नेता उनसे जुड़ जाएंगे यह भी संभव नहीं लगता है।

सिद्धांत सरकार, संगठन में चलता है

पिछले एक दशक से ज्यादा समय से भाजपा में यह सिद्धांत अपना लिया गया है कि अगर कोई नेता अपने दम पर या अपनी काबिलियत के दम पर बड़ा बना है

अजीत द्विवेदी

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद 209 दिन तक चले मंथन से भाजपा का संगठन चलाने के लिए जो 'रत्न' चुने गए हैं उनको देख कर कतई हैरानी नहीं हुई। अगर भाजपा संगठन में ऐसे पदाधिकारी नहीं चुने जाते या टीम ऐसी ही नहीं बनती तो हैरानी होती। ध्यान रहे जब कोई पार्टी सरकार में होती है तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन का कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। फिर भी भाजपा चूंकि संगठन वाली पार्टी मानी जाती है इसलिए एक कवायद दिखाई जाती है। उस कवायद से जो टीम बनी है वह बिल्कुल वैसी ही है, जैसी टीम पिछले एक दशक से सरकार और संगठन में बनाई जा रही है। दोनों जगह किसी अन्य चेहरे की जरुरत नहीं है। सरकार में नरेंद्र मोदी और संगठन में अमित शाह का ही मतलब है। बाकी सबको दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। यह नई टीम भी इसी सिद्धांत को व्यवहार रूप में प्रतीकित कर रही है।

ध्यान रहे पिछले एक दशक से ज्यादा समय से भाजपा में यह सिद्धांत अपना लिया गया है कि अगर कोई नेता अपने दम पर या अपनी काबिलियत के दम पर बड़ा बना है, अपना नाम बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, राष्ट्रीय दृष्टि रखता है तो उसको हाशिए में डालना है। इसके एकाध अपवाद हो सकते हैं। लेकिन यही सिद्धांत सरकार में चलता है, संगठन में चलता है और यहां तक कि चुनाव लड़ने में भी इसे ही लागू किया जाता है। बिल्कुल अनजान चेहरों को चुन कर आगे किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता है या राज्यसभा और विधान परिषद में भेजा जाता है। इनमें से ज्यादातर लोग विधायी कामकाज में क्या योगदान करते हैं यह बता पाना उनके खुद के लिए भी मुश्किल ही होगा।

राजनीति के रंगमंच पर अपनी संक्षिप्त भूमिका निभा कर थोड़े समय के बाद ये चेहरे नेपथ्य में चले जाते हैं। फिर उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन शुरुआत में जब इन्हें लाया जाता है तो प्रचार यह होता है कि बिल्कुल जमीनी स्तर से नेता खोजा गया है। असल में ऐसे नेताओं की कोई जमीन नहीं होती है। इसलिए वे बाद में जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं। इस बार भी ऐसे दर्जनों 'जमीनी नेता' पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर की कोई खास भूमिका नहीं रहेगी और थोड़े समय के बाद ये लोग कहां चले जाएंगे, वह किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ चुनिंदा लोग, जो पहले से संगठन का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोग, जिनको वापस संगठन में लाया गया है, वे ही काम करेंगे और जब चुनाव आएंगे तो संगठन के पदाधिकारियों से अलग के कुछ अन्य लोग चुनावी कामकाज में लगाए जाएंगे। वो चेहरे अलग होते हैं।

सो, 'जमीनी नेता' के नाम पर जो लोग संगठन में लाए गए हैं उनकी बात छोड़ दें तो कह सकते हैं कि यह एक कंजरवेटिव बदलाव है। कोई बड़ा प्रयोग करने से बचा गया है। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने या 'जेन जी' को महत्व देने के दबाव को दरकिनार किया गया है। भरोसे के कुछ चेहरों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है, जहां से वे शीर्ष नेताओं के साथ मिल कर संगठन के लिए काम करेंगे। वर्षों तक संगठन में काम कर चुके राम माधव को वापस लाया गया है। ऐसे ही स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। उपाध्यक्ष बना कर किनारे किए गए सौदान सिंह फिर से संयुक्त संगठन महामंत्री के तौर पर लाए गए हैं। बीएल संतोष और शिव प्रकाश की संगठन की जिम्मेदारी पहले जैसी ही रखी गई है। पिछले कई वर्षों से संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे विनोद तावड़े और सुनील बंसल को महामंत्री बनाए रखा गया है। तरुण चुघ महामंत्री पद से हटा दिए गए हैं लेकिन उनको पार्टी मुख्यालय का प्रभारी बना कर मुख्यधारा में रखा गया है।

भाजपा ने नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया है लेकिन स्पष्ट रूप से पलड़ा चुनावी राज्यों के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। चार चुनावी राज्यों से 18 पदाधिकारी बनाए गए हैं। कुल 65 पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात से 18 पदाधिकारी हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का दिखावा किया गया है फिर भी उनकी हिस्सेदारी 18 फीसदी तक ही पहुंच सकी है। कुल 12 महिलाओं को टीम में रखा गया है, जिनमें से छह उपाध्यक्ष हैं। आमतौर पर उपाध्यक्षों के पास कोई काम नहीं होता है। संगठन महामंत्री, संयुक्त संगठन महामंत्री और महामंत्रियों के 11 पदों में से सिर्फ एक पद महिला को मिला है। स्मृति ईरानी महामंत्री बनाई गई हैं। सोचें, 11 में एक यानी आधी आबादी को नौ फीसदी प्रतिनिधित्व! संगठन में सबसे युवा चेहरा हेमांग जोशी का है, जो 35 साल के हैं। नितिन नबीन की नई टीम बनने के बाद जितनी चर्चा इसमें शामिल किए गए चेहरों की है उससे ज्यादा चर्चा हटा दिए गए पदाधिकारियों की है। दीपक म्हस्के कैसे सोशल मीडिया के प्रभारी बने या कैसा काम करेंगे इस सवाल से ज्यादा चर्चा इसकी है कि अमित मालवीय क्यों हटा दिए गए? हेमांग जोशी भारतीय जनता युवा मोर्चा में कैसा काम करेंगे से ज्यादा चर्चा इस बात की है तेजस्वी सूर्या को क्यों हटाया गया है और आगे उनका क्या होगा? अनिल बलूनी के साथ मीडिया टीम में आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को लगाया गया है ये तीनों कैसा काम करेंगे इससे ज्यादा चर्चा में यह सवाल है कि संजय मयूख क्यों मीडिया टीम से हटाए गए? इन सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।

उधर भाजपा के कई बड़े, पुराने और चर्चित नेता पुनर्वास की उम्मीद में बैठे हैं। संगठन में शामिल नहीं किए जाने से उनको निराशा हुई होगी लेकिन उनमें से बहुत से लोग अब भी उम्मीद में होंगे कि क्या पता सरकार में जगह मिल जाए। अगले कुछ दिन में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। अभी प्रवक्ताओं की सूची आनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा होनी है और भाजपा की सबसे बड़ी ईकाई संसदीय बोर्ड का भी पुनर्गठन होना है। कहा जा रहा है कि मार्गदर्शक मंडल का भी विस्तार हो सकता है।

व्यंग्य

रहमान सरकार को डर क्यों?

शेख हसीना बेहद अलोकप्रिय हैं, अदालत उन्हें कठोरतम सजा सुना चुकी है, और उनकी पार्टी आवामी लीग का सांगठिक ढांचा ढह चुका है, तो उनके बयानों से तारिक रहमान सरकार को डर क्यों लगता है?

छात्र आंदोलन के कारण बांग्लादेश से भागने की आई नौबत के दो साल पूरा होने पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया। ये प्रेस कांफ्रेंस इसमें कही गई बातों से ज्यादा चर्चित इसलिए हुई, क्योंकि इससे संबंधित खबर देने पर बांग्लादेश में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तारिक रहमान सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया को पहले ही आगाह कर दिया था कि शेख हसीना के बयानों को जगह देना बांग्लादेश के कानून के मुताबिक 'अपराध' समझा जाएगा। वहां के मेनस्ट्रीम मीडिया ने आज्ञाकारी रुख अपनाया। नतीजतन, शेख हसीना के बयानों को ब्लैकआउट कर दिया गया। बात यहीं नहीं रुकी।

शेख हसीना की कथित तानाशाही के खिलाफ युवा विद्रोह के बाद हुए चुनाव से सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार ने इस घटना को भारत के साथ कूटनीतिक मुद्दा भी बना दिया। भारत सरकार से कहा गया कि वह शेख हसीना को प्रेस कांफ्रेंस की इजाजत ना दे, जिसके जवाब में भारत को इस मामले से अपने को पूरी तरह असंबंधित बताना पड़ा। सवाल यह है कि अगर शेख हसीना बेहद अलोकप्रिय हैं, अदालत उन्हें कठोरतम सजा सुना चुकी है, और उनकी पार्टी आवामी लीग का सांगठिक ढांचा ढह चुका है, तो उनके बयानों से तारिक रहमान की सरकार को डर क्यों लगता है? शेख हसीना ने दोहराया कि वे इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने के इरादे पर कायम हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि वहां जाने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 2024 में जिस व्यापक अशांति के कारण उनकी सरकार गिरी, वह स्वतःस्फूर्ति नहीं, बल्कि संगठित विद्रोह था, जिसका मकसद चुनावी ढांचे से बाहर जाकर अवैध तरीके से राजसत्ता पर कब्जा करना था। हसीना ये बातें पिछले दो साल से कहती रही हैं। बाकी उन्होंने जो कहा, राजनेता अक्सर ऐसी बातें करते हैं। आखिर इनसे बांग्लादेश की जमीनी सूरत पर क्या फर्क पड़ेगा? जब वहां सारी शक्तियां रहमान सरकार के पास हैं और प्रधानमंत्री को जन समर्थन का भरोसा है, तो उनकी सरकार एक प्रेस कांफ्रेंस से क्यों डर गई? क्या उसके ये तौर-तरीके तानाशाही नहीं हैं?

ब्लॉग

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार की एक प्रमुख मूल्य-समर्थन योजना है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बेहतर ढंग से लागू करने और किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2026-27 के लिए 7,200 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ, 'पीएम-आशा प्रभावी मूल्य-समर्थन उपायों को और सुदृढ़ बनाती है। 'आधार-आधारित प्रमाणीकरण, ई-नाम, ई-समृद्धि और ई-संयुक्ति सहित डिजिटल सुधारों ने पारदर्शिता और खरीद क्षमता में सुधार किया है। कृषि अवसंरचना कोष से मिली मदद और खरीद के दायरे को बढ़ाने से यह योजना और भी मज़बूत हुई है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ छोटे और हाशिये पर रह रहे किसानों सहित सभी किसानों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने सितंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में स्थिरता भी बनी रहे और साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिल सके। पीएम-आशा एक एकीकृत फ्रेमवर्क के तहत कई मूल्य समर्थन प्रणालियों को एक साथ लाती है। प्रत्येक प्रणाली को फसल और बाजार की स्थितियों के अनुसार लागू किया जाता है। यह योजना एमएसपी को लागू करने में मदद करती है और किसानों को मजबूरी में फसल बेचने से बचाती है। साथ ही, यह उपभोक्ताओं के लिए खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय को भी स्थिर बनाये रखती है। पीएम-आशा के तहत, खरीद की व्यवस्था प्रत्येक विपणन सत्र (मार्केटिंग सीज़न) से पहले ही शुरू हो जाती है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां और राज्य सरकारें फसलों के बाजार में पहुंचने से पहले ही खरीद के लिए ज़रूरी अवसंरचना तैयार कर लेती हैं। इस समन्वित दृष्टिकोण से खरीद का काम समय पर होता है और यह पूरे देश में एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाता है।

पीएम-आशा में मुख्य रूप से चार प्रमुख घटक शामिल हैं: मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस)। यह योजना कटाई के समय जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं, तब एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करती है। इसमें मुख्य रूप से दालें, तिलहन और खोपरा शामिल हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाती है। इसके लिए सिर्फ़ वे किसान पात्र हैं जिनके पास ज़मीन के वैध कागज़ात हैं; इससे बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधा लाभ सुनिश्चित होता है। उन्हें मजबूरी में फसल नहीं बेचनी पड़ती और कीमतों में भारी गिरावट के दौरान किसानों की आमदनी स्थिर बनी रहती है।

खरीद वर्ष 2024-25 से, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, दालों, तिलहन और खोपरा (कोपरा) की खरीद की अनुमति शुरुआत में किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कुल उत्पादन के 25त्न तक दी गई है। इस सीमा से अधिक की अतिरिक्त खरीद को सचिवों की समिति द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन के 25त्न तक मंजूरी दी जा सकती है। हालाँकि, घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति राज्य के उत्पादन के 100त्न तक दी गई है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) दालों, प्याज और आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाकर उपभोक्ताओं को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाता है। इसकी स्थापना प्रमुख कृषि-बागवानी उत्पादों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए की गई थी। कीमतों में अचानक वृद्धि को नियंत्रित करने और उन्हें आम जनता की पहुंच में (किफायती) रखने के लिए कटाई के मौसम में वस्तुओं की खरीद की जाती है और गैर-फसल (कम आवक वाले) मौसम में उन्हें बाजार में जारी किया जाता है। पीएसएफ को अब पीएम-आशा में विलय कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रबंधन अभी भी उपभोक्ता मामलों का विभाग ही करता है।

3. मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस)

मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत, किसानों की उपज को भौतिक रूप से खरीदा नहीं जाता है। इसके बजाय, अधिसूचित बाजारों में एमएसपी और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। यह भुगतान एमएसपी मूल्य के अधिकतम 15त्न तक हो सकता है। यह योजना मुख्य रूप से तिलहन के लिए उपयोग की जाती है और बड़े पैमाने पर खरीद संबंधी अवसंरचना की आवश्यकता को कम करती है। यह योजना किसानों को एमएसपी का संरक्षण प्रदान करते हुए बाजार-आधारित बिक्री को बढ़ावा देती है।

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को जल्दी खराब होने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों की एक श्रृंखला की खरीद के लिए बनाया गया है। इसमें टमाटर, प्याज और आलू जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू नहीं होता है। यह योजना तब लागू होती है जब बाजार की कीमतें पिछले सामान्य सत्र की दरों की तुलना में कम से कम 10त्न तक गिर जाती हैं। यह नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण के माध्यम से काम करती है। यह योजना विशेष रूप से बंपर पैदावार (अत्यधिक आवक) की स्थिति में उपयोगी होती है, जब आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) के तहत, पिछले कुछ वर्षों में बजट आवंटन लगातार बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में, इस योजना के तहत वास्तविक व्यय 5,437.99 करोड़ रुपये था। बजट 2025-26 में बढ़कर 6,941.36 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2026-27 में इसे और बढ़ाकर 7,200.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह दर्शाता है कि सरकार का ध्यान किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने और मूल्य आश्वासन तंत्र को सुदृढ़ करने पर है। पीएम-आशा के तहत शामिल योजनाओं की मदद से, उत्पादन लागत से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों की आय की सुरक्षा को मज़बूत करते हैं और साथ ही मुख्य फसलों की लगातार खेती को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 2026-27 में, धान (सामान्य) की लागत 1,627 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि इसका एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल था, जिससे 814 रुपये का लाभ (मार्जिन) मिला। सोयाबीन (पीला) की लागत 3,805 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि इसका एमएसपी 5,708 रुपये प्रति क्विंटल था, जिससे 1,903 रुपये का लाभ मिला। वर्ष 2026-27 में, गेहूं की उत्पादन लागत 1,239 रुपये प्रति क्विंटल और एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल है, जो 1,346 रुपये का लाभ (मार्जिन) सुनिश्चित करता है। वहीं, जूट की उत्पादन लागत 3,662 रुपये प्रति क्विंटल और एमएसपी 5,925 रुपये प्रति क्विंटल है, जो 2,293 रुपये का सबसे अधिक लाभ प्रदान करता है। एमएसपी का यह लाभकारी मार्जिन मूल्य आश्वासन को मजबूत करके और कृषि बाजारों में किसानों का भरोसा बढ़ाकर पीएम-आशा के लक्ष्यों को और मज़बूत करता है। कुल मिलाकर, एमएसपी लगातार अलग-अलग फसलों और सालों में उत्पादन लागत से ज़्यादा रहा है और पीएम-आशा किसानों को बेहतर कीमत दिलाकर इस प्रणाली को और मजबूत करता है। यह एक ऐसे सहायक ढांचे को रेखांकित करता है जो कृषि क्षेत्र में स्थिर आय और विकास को बढ़ावा देता है। सरकार ने कृषि विपणन और फसल कटाई के बाद की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एआईएफ और ई-नाम जैसी कई पहल शुरू की हैं। कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) ने 2,14,437 परियोजनाओं के लिए 96,426 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिससे 1,66,179 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म ने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,656 मंडियों को एकीकृत किया है, जिससे 4,94,847 करोड़ रुपये का व्यापार संभव हुआ है। इसके तहत ई-नाम पर 4,776 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को पंजीकृत किया गया है और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) से 7,334 एफपीओ को जोड़ा गया है। सरकार ने 25,081 कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ 992.6 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 50,249 गोदामों को भी स्वीकृति दी है।

हाल ही में पीएम-आशा में किए गए सुधारों के अंतर्गत किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधी खरीद, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के लिए परिवहन सहायता और बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत मूल्य अंतर भुगतान जैसी व्यवस्था की शुरुआत की गई है। बिहार में, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से पहली बार मसूर की संगठित खरीद शुरू की गई है। यह पीएम-आशा के तहत दलहन की खरीद को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, 48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को जोड़ा गया है। 10 अगस्त, 2026 तक एनसीसीएफ द्वारा 1,042.65 मीट्रिक टन मसूर की खरीद की गई है, जिसके लिए 358 किसानों का पंजीकरण किया गया और 285 किसानों को इसका सीधा लाभ मिला। इसी अवधि के दौरान, नेफेड ने भी 1,814.13 मीट्रिक टन मसूर की खरीद की है, जिसमें 495 किसानों का पंजीकरण किया गया और 455 किसानों को लाभ पहुँचाया गया।

छत्तीसगढ़ में, चल रही 200 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और 12 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के नेटवर्क के माध्यम से पीएम-आशा के तहत खरीद कार्यों को सुदृढ़ किया गया है। 10 अगस्त, 2026 तक एनसीसीएफ ने 18,392.228 मीट्रिक टन चना, 22.231 मीट्रिक टन मसूर और 1,035.0205 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है। इसके तहत 21,721 किसानों का पंजीकरण किया गया और 13,790 किसानों को लाभ पहुँचाया गया। इसी अवधि के दौरान, नेफेड ने 17,020.65 मीट्रिक टन चना और 355.05 मीट्रिक टन मसूर की खरीद की है। इसमें 46,146 किसानों का पंजीकरण किया गया और 13,673 किसानों को इसका लाभ मिला। इन पहलों ने एमएसपी खरीद को मजबूत किया है, बाजार तक पहुंच में सुधार किया है और क्षेत्र-विशेष में दलहन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद की है।

हत्या के केस में पड़ोसी को फंसाने के लिए बेटी को मार डाला, पिता सहित पांच लोगों को उम्रकैद

आर्यावर्त संवाददाता

पीलीभीत। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में पड़ोसी को हत्या के मामले में फंसाने की साजिश में नौ वर्षीय बेटी अनम की हत्या करने वाले पिता अनीस को अदालत ने अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि अनीस के तीन भाइयों शादाब, नसीम व सलीम और पिता शहजादे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय विजय कुमार हिमांशु ने मामले को जघन्यतम मानते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में अनीस को जीवित रहते जेल से रिहा न किया जाए। सभी दोषियों पर 1,10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

पड़ोसी शकील ने अनीस और उसके भाई शादाब के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। शकील केस वापस नहीं ले रहा था। इस मामले में कोर्ट से वारंट भी जारी हो गया था। दो दिसंबर 2022 को सरेन्दा पट्टी में लगे उर्स मेले के दौरान अनीस ने अपने पिता और तीन भाइयों के साथ मिलकर शकील को हत्या के झूठे केस में फंसाने की साजिश रची।

चाकू से फाड़ा था पेट

ये लोग मासूम अनम को मेले से पास के खेत में ले गए और वहां नींद की गोली खिला दी। इससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद अनीस ने उसके सिर पर ईंट से वार किया। फिर अनम के हाथ-पैर पकड़े गए और चाकू से गोदकर पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के तुरंत बाद पिता ने खुद ही विरोधी शकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।

वीडियो बनाने से संदेह के घेरे में आए थे आरोपी

पुलिस जांच में बताया गया कि वारदात के अगले दिन अनम की तलाश का ढोंग करते हुए चाचा नसीम घटनास्थल पर पहुंचा। वहां से इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की बजाय वह वीडियो बनाने लगा। लहूलुहान अनम का वीडियो बनाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने परिजनों को संदेह के दायरे में लिया। पुलिस ने तत्काल चार संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। खून से सनी एक पैंट भी बरामद की। सख्ती से पूछताछ के बाद पिता सहित पांचों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध, क्षमा योग्य नहीं

अदालत ने मामले की परिस्थितियों को गंभीर और जघन्य मानते हुए कहा कि मासूम बच्ची को नींद की गोली देकर अचेत करना, उसके बाद ईंट और चाकू से हत्या करना और शव को छिपाकर जांच को गुमराह करना अत्यंत गंभीर अपराध है। यह क्षमा योग्य नहीं है।

डंपर ने कार को मारी टक्कर, लखनऊ के चार लोगों की मौत, बच्ची की हालत गंभीर

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी में मंगलवार को डंपर और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। जबकि, आठ साल की हुदा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार लोग लखनऊ के कमता इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार आदर्श नगर, कमता निवासी मोहम्मद शरीफ के नाम पर है।

हादसा मसौली थाना क्षेत्र के बांदा-बहराइच मार्ग पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, बिंदौरा चौराहे के पास कार मुड़ रही थी, तभी बाराबंकी तरफ से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार लोग भीतर ही फंस गए। राहगीरों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई।

घायलों को बड़ा गांव सीएचसी भेजा। वहां चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। मौत की पुष्टि बड़ागांव सीएचसी के अधीक्षक डॉ. राधेश्याम गौड़ ने की है। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर आवागमन भी ठप रहा। हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है।

तीन तस्कर गिरफ्तार 5 पिस्टल, 7 तमंचे बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। थाना मछलीशहर ऑपरेशन वज्रपात के तहत पुलिस ने अवैध असलहा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। मछलीशहर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच देशी पिस्टल, सात अवैध तमंचे और दो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं।पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर ताजुद्दीनपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन संदिग्धों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों के अंतरजनपदीय असलहा तस्करी गिरोह से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव निवासी शिव प्रकाश मिश्रा और मनकामेश्वर मिश्रा तथा खोजापुर निवासी प्रियांशु शुक्ला के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अपने गृह जनपद से अवैध असलहे लाकर जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत आसपास के जिलों में उनकी तस्करी करते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह को असलहों की सप्लाई कहां से मिलती थी और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाता था। गिरोह का मुख्य सरगना सुनील दूबे निवासी हरसड़, थाना हलिया, मिर्जापुर बताया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी मनकामेश्वर मिश्रा के खिलाफ मिर्जापुर के कछवा थाने में आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है।

इस्लाम में यह अनिवार्य नहीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रा यह साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक प्रमाण पेश नहीं कर सकी कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड एक समान, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन तथा संस्थान की पहचान बनाए रखने के मकसद से लागू किया गया है, तो उसमें व्यक्तिगत आधार पर बदलाव की मांग नहीं की जा सकती।

क्या है हिजाब से जुड़ा मामला

मामला प्रयागराज के अत्तारसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 11वीं कक्षा में प्रवेश देने और निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का दावा था कि वह कक्षा छह से 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ी और इस दौरान सिर पर स्कार्फ पहनती रही, जिस पर स्कूल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, स्कूल ने साफ किया कि सभी छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म लागू है। स्कूल के मुताबिक, किसी एक छात्रा को अलग से छूट देने से अनुशासन और ड्रेस कोड की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट ने किया कर्नाटक HC के फैसले का जिक्र

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहले की कक्षाओं में स्कार्फ पहनने पर स्कूल की ओर से आपत्ति नहीं किए जाने से छात्रा को भविष्य में भी इसे पहनने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं हो जाता। कोर्ट ने इस मामले में देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया। बेंच ने खास तौर से कर्नाटक हाईकोर्ट की 2022 की फुल बेंच के फैसले को अहम और प्रभावशाली माना, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट के आयशा शिफा मामले में फैसला बंटा हुआ था और इस मुद्दे पर अभी तक ऐसा अंतिम फैसला नहीं आया है, जो पूरे विवाद को निर्णायक रूप से सुलझाता हो। इसके बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है।

समानता और अनुशासन की बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म का मकसद छात्रों के बीच समानता, अनुशासन, संस्थान की पहचान और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना भी है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छात्रा की रिट याचिका खारिज कर दी।

मोबाइल में देखा सीक्रेट हाउस गेम, टास्क के लिए घर से भागे दो बच्चे, ईंट भट्ठे के पास बनाया था सीक्रेट हाउस

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ में यूट्यूब पर सीक्रेट हाउस गेम्स देखकर दो बच्चे लापता हो गए, जिससे परिजनों और पुलिस के पसीने छूट गए। जेन अल्फा जनरेशन पर मोबाइल के बुरे असर का यह एक और उदाहरण सामने आया है।परिजनों की सूचना पर पुलिस ने कई घंटे तक मशक्कत की। आखिरकार, मिशन शक्ति की टीम ने बच्चों को बरामद कर लिया। यह घटना थाना हस्तिनापुर क्षेत्र की है।

दोनों बच्चे मोबाइल एडिक्टेड थे। उन्होंने एक ईंट भट्ठे के पास जाकर सीक्रेट हाउस बनाया था और उसमें 24 घंटे तक छिपने का चैलेंज लिया था। थाना हस्तिनापुर और मवाना सर्कल की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लोगों से पूछताछ की और उसके बाद यह मिशन सफल हो सका।

वहीं, पुलिस अधिकारियों की मानें तो बच्चों के मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया, जिसके चलते दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि एक महिला ने सूचना दी थी कि यूट्यूब पर एक गेम चलता है, जिसे खेलने के दौरान उनके दो बच्चे कहीं चले गए हैं।

महिला ने पुलिस को आशंका जताते हुए बताया कि बच्चे खेलने के दौरान कहीं छिप गए हैं। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की गई और सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया और परिवार के सुपुर्द कर दिया गया।

71 प्राविधिक सहायकों को मिले नियुक्ति पत्र

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्तिध्चयन पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना गया। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बताया कि जनपद में कुल 71 प्राविधिक सहायकों का चयन हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी ने भी नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों को शुभकामनाएं दीं और कृषि एवं किसान हित की

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। संचालन डिप्टी पीडी आत्मा डॉ. रमेश चंद्र यादव ने किया। उप कृषि निदेशक अश्वनी सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार समेत अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे।

जिला कारागार के कैदी की मौत

जौनपुर। जिला कारागार में सजा कांट रहे कैदी की तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि आजमगढ जनपद के रानीकीसराय थाना क्षेत्र के चकवारा गांव निवासी 64 वर्षीय जैनू यादव आजमगढ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से हत्या के एक मुकदमें में आजीवन कारागार की सजा दी गई थी। वर्ष 2008 आजमगढ जेल में सजा कांट रहे जैनू यादव को कुछ माह पूर्व जिला कारागार जौनपुर में स्थांनात्रित किया गया था। सोमवार आचानक तबियत खराब होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में शाम लगभग 7 बजे भर्ती कराया गया, जहां रात्री लगभग 12 बजे उनकी मौत हो गई। कारागार पुलिस लाश को लाश घर में रखकर परिजनों को सूचना दिया। मंगलवार सुबह परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गयें। पुलिस ने मौत का सही कारण जानने के लिए कैदी की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

नोएडा में एक्वा से ब्लू लाइन तक नहीं चलना पड़ेगा पैदल, एयरपोर्ट जैसी मिली सुविधा

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। Noida Sector 51-52 Metro Skywalk: नोएडा के सेक्टर-51 और 52 मेट्रो स्टेशन के बीच बने स्काईवॉक को आज से शुरू कर दिया जाएगा। इससे नोएडा सेक्टर-51 (एक्वा लाइन मेट्रो) और सेक्टर-52 (ब्लू लाइन मेट्रो) के बीच सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा अथॉरिटी ने इसे शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको शुरू करने के निर्देश नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने सीविल विभाग के अधिकारियों को 16 अगस्त को ही दिए गए थे, लेकिन ये आज से शुरू किया जाएगा।

लोगों की सुविधा के लिए इसमें एयरपोर्ट की तरह ट्रेवलेटर भी लगाए गए हैं। इस स्काईवॉक का निर्माण छह माह पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको बनाने में लगभग तीन

का समय लग गया। इस स्काईवॉक का निर्माण कार्य साल 2023 में शुरू किया गया था। स्काईवॉक के सेक्टर-51 स्टेशन की तरफ जोड़े जाने वाली जगह में बदलाव किया गया। इसी के कारण आठ महीने तक स्काईवॉक का काम नहीं हुआ।

यह स्काईवॉक है 460 मीटर लंबा

यह स्काईवॉक 460 मीटर लंबा है और पूरी तरह से एसी युक्त है। जानकारी के अनुसार, इस स्काईवॉक को दिल्ली कीइंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। यह ।5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगा। इसमें में 50-50 मीटर पर 10 ट्रैवलेटर लगाए गए हैं। इनमें से 5 ट्रैवलेटर एक तरफ से और दूसरी तरफ चलेंगे। इससे सफर करने वाले यात्री दोनों स्टेशनों के बीच आसानी से आ जा सकेंगे।

अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा

इतना ही नहीं यात्रियों को स्टेशन बदलने के लिए नीचे उतरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बता दें अब तक सेक्टर-51 से सेक्टर-52 मेट्रो तक जाने के लिए लोग पैदल या फिर बाहर से रिक्शा और ऑटो लेकर जाते थे। रोजाना आवाजाही करने वाले यात्रियों को इससे परेशानी होती थी। अब रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उनको धूप में नहीं चलना पड़ेगा।

मथुरा में कन्हैया के जन्मोत्सव पर आसमान भी होगा कृष्णमय, 500 ड्रोन दिखाएंगे कृष्ण लीला

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव एक नए और भव्य रूप में नजर आएगा। इस पावन धरा पर भगवान श्रीकृष्ण ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि में कंस के कारागार में अवतार लिया था, उसी पवित्र जन्मस्थल की धरती के साथ अब आसमान भी कृष्णमय होगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात पहली बार 500 ड्रोन के जरिए भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का भव्य दृश्य आसमान में प्रदर्शित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि परिषद श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में 4 सितंबर की रात 9 से

10 बजे के बीच करीब 15 मिनट का ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। 500 ड्रोन आसमान में एक साथ उड़कर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं से जुड़े दृश्य और आकृतियां बनाएंगे। यह शो करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देगा। इस तरह जन्मभूमि के आसपास मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आसमान में होने वाली इस अनूठी कृष्ण लीला के साक्षी बन सकेंगे।

हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं मथुरा

उन्होंने कहा कि जन्मभूमि पर जन्माष्टमी का अपना विशेष महत्व है। भगवान श्रीकृष्ण ने इसी पावन भूमि पर अत्याचारी कंस के कारागार में अवतार लेकर अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का संदेश दिया था। यही कारण है कि देश-दुनिया के कृष्ण भक्तों के लिए मथुरा की जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भगवान के अवतरण की पावन स्मृति से जुड़ने का अवसर भी है। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में जन्मभूमि मंदिर में होने वाला जन्माभिषेक देखने के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। यहां पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस बार मथुरा में 500 ड्रोन के माध्यम से कन्हैया के जन्म की लीलाओं को आसमान में देखने का भी अवसर मिलेगा। इस तरह मथुरा की जन्माष्टमी मथुरा में इस बार श्रद्धा, आस्था और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम की साक्षी बनेगी।

अयोध्या, बनारस और सोमनाथ पैटर्न पर मथुरा में होगा ड्रोन शो

धार्मिक आयोजनों में ड्रोन शो का प्रयोग अब नया आकर्षण बन चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर ड्रोन शो के जरिए भगवान श्रीकृष्ण की 12 लीलाओं के दृश्य आसमान में प्रदर्शित किए जा चुके हैं। वहीं गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्य शो आयोजित हुआ, जिसमें सोमनाथ के इतिहास, भगवान शिव और भारतीय संस्कृति से जुड़े दृश्य आसमान में उकेरे गए। ऐसे में मथुरा में जन्मभूमि की पृष्ठभूमि में 500 ड्रोन से कृष्ण जन्म और लीलाओं का प्रदर्शन इस तकनीक को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा प्रयोग है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, प्रयागराज और बनारस में भी ड्रोन शो का आयोजन हो चुका है।

नवनियुक्त कुलपति ने पदभार ग्रहण किया

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पूर्व कुलपति प्रो. वंदना सिंह से कार्यभार संभाला। प्रो. राकेश कुमार सिंह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और उच्च शिक्षा प्रशासन में कुलसचिव, परीक्षा कार्य से जुड़े दायित्व, छात्र कल्याण तथा योजना एवं विकास जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। प्रो. सिंह इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय से आए हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य पूर्वांचल विश्वविद्यालय को तकनीक-सक्षम, पारदर्शी, जवाबदेह और विद्यार्थी-केंद्रित उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विश्वविद्यालय में पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम, प्रवेश, शोध, छात्र सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुगम बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। शोध को प्रोत्साहन मिले और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होकृइसके लिए एक मजबूत डिजिटल प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाएगा। इंटरनेट और सुरक्षा जैसी बुनियादी छात्र सुविधाओं की लगातार निगरानी हो। विद्यार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा। सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी और संबद्ध महाविद्यालय इस परिवर्तन यात्रा के सहभागी होंगे। इसके बाद मुक्तांगन परिसर में कुलपति जी ने पौधरोपण किया।

बार-बार फोन चेक करने की आदत है? जानिए इसके कारण

कई लोग बार-बार अपने फोन को देखते रहते हैं। यह आदत न केवल समय की बर्बादी कर सकती है, बल्कि मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। इस लेख में हम इस आदत के पीछे की मानसिक वजहों का पता लगाएंगे और जानेंगे कि क्यों लोग बार-बार अपने फोन को देखते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसके अलावा इस आदत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे।

जानकारी का बोझ

आजकल हमारे पास हर तरह की जानकारी एक क्लिक की दूरी पर मौजूद रहती है।

सोशल मीडिया, समाचार ऐप और अन्य माध्यमों के जरिए हम हर पल नई जानकारियों से जुड़े रहते हैं।

यह जानकारी इतनी अधिक होती है कि उसे बार-बार देखने की जरूरत महसूस होती है।

इससे हमें लगता है कि हम कुछ जरूरी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है।

सामाजिक जुड़ाव की चाह

सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहना हमारे लिए एक तरह का सामाजिक जुड़ाव बनाता है।

हम चाहते हैं कि हमारे पोस्ट्स पर लाइक्स आएं, टिप्पणियां मिलें और लोग हमारे साथ बातचीत करें।

इस चाहत के कारण हम बार-बार अपने फोन को देखते रहते हैं, ताकि कहीं कोई टिप्पणी या संदेश न छूट जाए।

यह हमारे लिए मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका जैसा बन जाता है।

खोने का डर

खोने का डर एक ऐसी भावना है, जो हमें हमेशा अपडेट रहने पर मजबूर करती है।

हम चाहते हैं कि हम हर जरूरी खबर, घटना या चलन से वाकिफ रहें, ताकि हमें ऐसा न लगे कि हम कुछ अहम छोड़ रहे हैं।

इस डर के कारण हम बार-बार अपने फोन को देखते रहते हैं, जिससे हमारी यह आदत बन जाती है।

इससे हमें लगता है कि हम किसी भी जरूरी जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे।

काम का दबाव

आजकल काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ऑफिस ईमेल्स और संदेश पर लगातार नजर रखते हैं।

अगर कोई जरूरी मेल आया हो या कोई जरूरी संदेश आया हो तो उसे तुरंत देखना जरूरी हो जाता है।

इस वजह से लोग अपने फोन को बार-बार देखते रहते हैं, ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए। इससे उनकी यह आदत बन जाती है और वे हमेशा काम के तनाव में रहते हैं।

मनोरंजन का साधन

फोन का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जैसे वीडियो देखने, खेल खेलने या संगीत सुनने आदि। ये सभी गतिविधियां हमें खुश रखती हैं, लेकिन इनकी आदत लग जाती है।

हम हर समय अपने फोन पर कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारा समय सही तरीके से उपयोग हो रहा है।

इन सभी कारणों से बार-बार फोन देखने की आदत बन जाती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है।

इन 5 ब्यूटी सीक्रेट्स को आजमाएं, महंगा दिखेगा आपका लुक

महंगा दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार महंगे कपड़े या गहने पहनें। कुछ छोटे-छोटे ब्यूटी सीक्रेट्स और स्मार्ट टिप्स से आप बिना ज्यादा खर्च किए भी महंगी और आकर्षक दिख सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही 5 आसान और प्रभावी ब्यूटी सीक्रेट्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी झंझट के हर मौके पर सबसे खूबसूरत दिखेंगी।

सही मेकअप चुनें

सही मेकअप का चुनाव आपके पूरे लुक को बदल सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा महंगा दिखे तो हल्का और प्राकृतिक मेकअप चुनें।

फाउंडेशन हमेशा आपकी त्वचा के रंग से मेल खानी चाहिए ताकि चेहरे पर कोई अंतर न दिखे।

लिपस्टिक का चुनाव भी सोच-समझकर करें। गहरे रंग की लिपस्टिक हमेशा महंगे और आकर्षक दिखती हैं।

इसके अलावा आंखों के लिए हल्का काजल और मस्कारा लगाएं ताकि आंखें बड़ी और खूबसूरत लगें।

बालों की देखभाल करें

सुंदर और चमकदार बाल हमेशा महंगी दिखाते हैं। इसके लिए नियमित तौर पर तेल की मालिश करें और हफ्ते में कम से कम दो बार बाल धोएं।

बालों के लिए मास्क भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके बालों को पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।

इसके अलावा बालों को धूप से बचाने के लिए स्कार्फ या टोपी पहनें। यह न केवल आपके बालों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा।

खुशबू का सही चयन करें

खुशबू भी आपके लुक को खास बना सकती है। एक अच्छी खुशबू आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको पूरे दिन ताजगी का एहसास दिलाती है।

अपने शरीर की गंध को छिपाने के लिए खुशबू का इस्तेमाल करें, जिससे आप हमेशा महकती रहें।

इसके अलावा खुशबू का सही चयन भी जरूरी है। हल्की और ताजगी भरी खुशबू का इस्तेमाल करें जो आपको दिनभर ताजगी दें और आपके व्यक्तित्व को निखारें।

सही कपड़ों का चयन करें

कपड़े चुनते समय उनकी फिटिंग पर ध्यान दें। अच्छे फिटिंग वाले कपड़े हमेशा महंगे और आकर्षक दिखते हैं। ढीले-ढाले कपड़े न पहनें क्योंकि वे आपको साधारण दिखा सकते हैं।

इसके अलावा कपड़ों का रंग भी अहम होता है। गहरे रंग जैसे काला, नीला या लाल हमेशा महंगे दिखते हैं।

इसके साथ ही सरल डिज़ाइन वाले कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वे आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और आपको अधिक आकर्षक बनाते हैं।

एक्सेसरीज का सही उपयोग करें

एक्सेसरीज आपके लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सोने या चांदी की नहीं बल्कि सरल लेकिन स्टाइलिश एक्सेसरीज चुनें जैसे मोती का हार या चांदी का कंगन जो आपको महंगा दिखाएं बिना किसी बोझिलता के।

इन सरल टिप्स को अपनाकर आप न केवल हर मौके पर सबसे खूबसूरत दिखेंगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे। याद रखें, सच्ची सुंदरता आत्मविश्वास में छिपी होती है!

एक दिन की लें लीव और 4 दिन घूमने का मजा, 28 से 31 तक लॉन्ग वीकेंड में यहां जाएं

भागदौड़ भरी जिंदगी से सुकून के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आने वाले लॉन्ग वीकेंड पर 4 दिन के लिए घूमने जा सकते हैं। तो चलिए इस आर्टिकल में जान लेते हैं कि आप किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जॉब वाले लोग ट्रिप प्लान करने की सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर वीकेंड के साथ एक फेस्टिव ऑफ हो तो आप आराम से ट्रिप पर जा सकते हैं, बस उसमें 1 दिन की छुट्टी एड करनी होगी। 28 अगस्त 2026 को, शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ रहा है। इसके बाद शनिवार और रविवार का वीकेंड है। आप 31 अगस्त की छुट्टी लेकर ट्रिप पर जा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दिल्ली-एनसीआर से आप 4 दिन के लिए कहां-कहां की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

अगर आप 27 का ऑफ लेते हैं तो रक्षाबंधन आपको अपनी ट्रिप के दौरान ही सेलिब्रेट करना होगा, लेकिन 31 की छुट्टी लेते हैं तो राखी सेलिब्रेट करने के बाद उस दिन ट्रिप के लिए निकल सकते हैं और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अगले दिन से घूमना-फिरना कर सकते हैं।

पिंक सिटी जयपुर

आप दिल्ली से राजस्थान के जयपुर घूमने जा सकते हैं या फिर रींगस जाकर पहले खाटूश्याम के दर्शन करें और फिर यहां से बस से जयपुर घूमने निकल जाएं। ये जगह अपनी राजपुताना शाही संस्कृति और विरासत के लिए भी जानी जाती है। यहां की सबसे प्रसिद्ध जगह हवा महल घूमने के अलावा आप आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर-मंतर, जल महल जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

ऋषिकेश को करें एक्सप्लोर

अगर आप हरियाली भरी पहाड़ की वादियों के साथ ही आध्यात्मिकता को भी अपनी ट्रिप में एड करना चाहते हैं तो इस लॉन्ग वीकेंड पर ऋषिकेष घूमने जा सकते हैं। ये जगह ज्यादातर प्रमुख शहरों से कनेक्ट है, इसलिए ट्रेवल करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। सबसे बेस्ट रहेगा कि इस तरह जाएं कि बिल्कुल मॉर्निंग में पहुंच जाएं। पहले हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान और आरती करें। इसके बाद ऋषिकेश के लिए निकल जाएं। यहां पर त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, नीर गढ़ वाटर फॉल जैसी जगहों को एक्सप्लोर करें। समय हो तो नीलकंठ महादेव जा सकते हैं और राफ्टिंग भी कर सकते हैं।

कसौली घूमने जाएं

आप हिमाचल प्रदेश के कसौली जा सकते हैं। दिल्ली से यहां पहुंचने में 5-6 घंटे लगते हैं। यहां आकर आप मंकी पॉइंट जरूर जाएं। ये कसौली की सबसे ऊंची चोटी है। ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन हरियाली के साथ ही शांति से भरा हुआ है। यहां पर आप गिलहर्ट ट्रेल, सनसेट पॉइंट, लवर्स लेन, मॉल रोड, कसौली ब्रेवरी जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण की नगरी को करें एक्सप्लोर

आप 4 दिन की इस छुट्टी में बरसाना एक्सप्लोर करेंगे तो कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से आपको बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी। यहां पर ज्यादातर लोग बस बांकेबिहारी के दर्शन करके चले जाते हैं। यहां असली मजा तो गलियों में छुपे प्राचीन मंदिरों को एक्सप्लोर करने में है। वृंदावन के साथ ही बरसाना, मथुरा भी घूमने जाएं। यमुना केसी घाट, निधिवन,प्रेम मंदिर, लाड़ली जी मंदिर, कीर्तिका मदिर, प्रेम सरोवर, प्रिया कुंड, जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर घूमने जाएं।

30 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाना है? हर महीने कितने की करनी होगी एसआईपी

नई दिल्ली, एजेंसी। रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार करना सुनने में भले ही एक बड़ा लक्ष्य लगे, लेकिन सही समय पर निवेश शुरू कर दिया जाए और लंबे समय तक नियमित निवेश जारी रखा जाए तो कंपाउंडिंग की ताकत से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खासतौर पर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लंबी अवधि का निवेश रिटायरमेंट प्लानिंग का एक प्रभावी तरीका बन सकता है। हालांकि, निवेश शुरू करने की उम्र जितनी कम होगी, उतना अधिक समय कंपाउंडिंग के लिए मिलेगा और हर महीने निवेश की जाने वाली रकम अपेक्षाकृत कम हो सकती है। आज हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताते हैं कि अगर कोई 30 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाना चाहता है तो उसे हर महीने कितने रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी।

अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, तो उसके पास 60 साल की उम्र तक 30 साल का समय होता है। वहीं, 25 साल की उम्र वाले व्यक्ति के पास करीब 35 साल का समय होता है। जबकि 35 साल की उम्र वाले को 25 साल और 40 साल की उम्र में शुरुआत करने वाले निवेशक को केवल 20 साल का समय मिलता है। इसके अलावा मौजूदा आय, भविष्य में वेतन वृद्धि, मासिक खर्च, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, स्वास्थ्य खर्च और रिटायरमेंट के बाद की जरूरतें भी यह तय करती हैं कि वास्तव में कितना रिटायरमेंट फंड चाहिए।

यदि 12 प्रतिशत सालाना औसत रिटर्न और पूरी अवधि के दौरान बिना एसआईपी बढ़ाए एक निश्चित मासिक निवेश का अनुमान लगाया जाए, तो 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए लगभग 14,500 रुपए प्रति माह की एसआईपी करनी पड़ सकती है। 30 साल तक लगातार इस रकम का निवेश करने पर कुल निवेश करीब 52.20 लाख रुपए होगा, जबकि अनुमानित रिटर्न के साथ रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 5.12 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

वहीं, 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक का कॉर्पस तैयार करने के लिए करीब 8,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी की जरूरत पड़ सकती है। 35 साल तक निवेश करने पर उसका कुल योगदान लगभग 33.60 लाख रुपए होगा और 12 प्रतिशत अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर कॉर्पस करीब 5.20 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

अगर निवेश की शुरुआत 35 साल की उम्र में की जाती है, तो निवेश की अवधि घटकर 25 साल रह जाती है। ऐसे में 5 करोड़ रुपए के आसपास का रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए करीब 26,500 रुपए प्रति माह की एसआईपी करनी पड़ सकती है। इस दौरान कुल निवेश लगभग 79.50 लाख रुपए होगा और अनुमानित कॉर्पस करीब 5.03 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसी तरह 40 साल की उम्र में शुरुआत करने वाले व्यक्ति को केवल 20 साल में यह लक्ष्य हासिल करने के लिए करीब 50,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी करनी पड़ सकती है। इस स्थिति में कुल निवेश लगभग 1.20 करोड़ रुपए होगा और अनुमानित कॉर्पस करीब 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

इन आंकड़ों से साफ है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा फायदा जल्दी निवेश शुरू करने से मिलता है। जितनी जल्दी एसआईपी शुरू होगी, उतना ही ज्यादा समय निवेश को कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा और लक्ष्य हासिल करने के लिए मासिक निवेश का बोझ कम हो सकता है। हालांकि, 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय करते समय महंगाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज जो मासिक खर्च 50,000 रुपए है, वह 25 या 30 साल बाद महंगाई के कारण काफी अधिक हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों का अनुमान हमेशा भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए।

इसके साथ ही, यह भी समझना जरूरी है कि 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न केवल एक अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इक्विटी और इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड में बाजार के उतार-चढ़ाव का असर पड़ सकता है और वास्तविक रिटर्न अनुमान से कम या अधिक हो सकता है।

ऐसे में बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि केवल एक निवेश विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश को अलग-अलग एसेट क्लास में बांटना बेहतर हो सकता है। पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों के साथ म्यूचुअल फंड, शेयर और ईटीएफ जैसे बाजार से जुड़े निवेश साधनों का संतुलित मिश्रण लंबे समय में रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को अधिक मजबूत बना सकता है।

बच्चों के आधार अपडेट को लेकर यूआईडीएआई की बड़ी चेतावनी : बायोमेट्रिक अपडेट इस दिन तक मुफ्त, बाद में लग सकता है शुल्क

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अभिभावकों और संरक्षकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) समय रहते पूरा करा लें। यूआईडीएआई के अनुसार, 5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा 30 सितंबर तक पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। इसके बाद इस सुविधा को आगे बढ़ाने या शुल्क लागू करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

यूआईडीएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए कहा है कि बच्चों के 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है। यह अपडेट स्कूल में प्रवेश, परीक्षाओं, छात्रवृत्ति आवेदन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के दौरान पहचान सत्यापन को आसान बनाता है। प्राधिकरण ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कराएं। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, जब किसी बच्चे का आधार पांच वर्ष की आयु से पहले बनता है, तब उसमें केवल उसकी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो दर्ज की जाती है। उस समय बच्चे के फिंगरप्रिंट और आईरिस (आंखों की पुतली) स्कैन नहीं लिए जाते, क्योंकि कम उम्र में ये बायोमेट्रिक पहचान लगातार विकसित हो रही होती है।

इसी कारण बच्चे के पांच वर्ष का होने पर पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है। इसके बाद 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक होता है, ताकि उसका आधार रिकॉर्ड अद्यतन और सटीक बना रहे। आधार भारत में पहचान सत्यापन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। छात्रों के लिए इसका उपयोग स्कूल में प्रवेश, बोर्ड परीक्षाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं, सरकारी सहायता कार्यक्रमों और विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। समय पर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने की स्थिति में भविष्य में पहचान सत्यापन से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए यूआईडीएआई लगातार अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक कर रहा है।

यूआईडीएआई ने सितंबर 2025 में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत अब तक देशभर में लगभग 2 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पूरे किए जा चुके हैं। प्राधिकरण के अनुसार, यह अभियान 1.56 लाख से अधिक स्कूलों तक पहुंच चुका है और इसका उद्देश्य अधिकतम बच्चों को इस सुविधा से जोड़ना है। इसी पहल के तहत 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट दी गई थी, जिसे वर्तमान में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक नजदीकी आधार केंद्रों पर जाकर बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निशुल्क कराया जा सकता है। हालांकि इस समयसीमा के बाद शुल्क माफी जारी रहेगी या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम दिनों की भीड़ से बचते हुए जल्द से जल्द अपने बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कराएं।

मेल वोटिंग के खिलाफ आदेश पर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वैधता पर अभी फैसला बाकी

वॉशिंगटन, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर (कार्यकारी आदेश) से जुड़े मामले में ट्रंप प्रशासन का साथ दिया, जिसमें मेल-इन वोटिंग पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि तेजी से आ रहे मिडटर्म चुनावों से पहले इसे कितना लागू किया जा सकेगा। इस फैसले के बाद कोर्ट में और चुनौतियां पेश की जा सकती हैं, जिनसे ट्रंप के आदेश पर अमल और धीमा हो सकता है। ऐसे ही कुछ और मामले पहले ही दायर किए जा चुके हैं। US पोस्टल सर्विस ने पिछले हफ्ते बताया था कि वह इस आदेश को कैसे लागू करेगी, लेकिन बड़े बदलाव करने के लिए समय कम बचा है क्योंकि कुछ राज्यों में कुछ ही हफ्तों में वोटरों को मेल बैलेट भेजे जाने शुरू हो जाएंगे।

ट्रंप के आदेश की वैधता पर फैसला अभी बाकी

कोर्ट के कंजर्वेटिव बहुमत ने ट्रंप के आदेश की वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि यह कहा कि राज्यों को इसे चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है। बहुमत ने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश में लिखा, इस अर्ज़ी पर कोर्ट के फैसले का मतलब यह नहीं है कि आदेश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम कानूनी ही होगा। इस बारे में तो समय ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के तीन लिबरल-विचारधारा वाले जजों ने इस फैसले से असहमति जताई। मेल के जरिए वोटिंग लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर रही है। उनका दावा है कि इससे धोखाधड़ी होती है, जबकि इसके उलट मजबूत सबूत मौजूद हैं और खुद ट्रंप भी इस वोटिंग तरीके का इस्तेमाल कर चुके हैं।

वोटिंग से जुड़ी कई चुनौतियां

यह मामला जजों के सामने वोटिंग से जुड़ी कई चुनौतियों में से एक हो सकता है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक इमरजेंसी अपील दायर करके हाई कोर्ट से मिड-टर्म चुनाव से पहले इन बदलावों को लागू करने की इजाज़त मांगी थी। मार्च में साइन किए गए ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उनके प्रशासन से योग्य वोटरों की लिस्ट बनाने और US पोस्टल सर्विस को सिर्फ उन लिस्ट में शामिल लोगों तक ही मेल बैलेट पहुंचाने का आदेश दिया गया है।

ट्रंप के आदेश को रोकने के लिए केस

23 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया के डेमोक्रेटिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए केस किया। उनका तर्क था कि संविधान राज्यों और कांग्रेस को चुनाव कराने की शक्ति देता है, और ट्रंप के बदलावों से अव्यवस्था और पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग हो सकता है। राज्यों के वकीलों ने लिखा, इस पतझड़ में होने वाले चुनावों के इतने करीब ऐसे बड़े बदलावों को लागू करने के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। दर्जनों राज्य और स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने अपनी राय रखते हुए जजों से कहा कि जब चुनाव की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं, तो इस आदेश पर रोक बनाए रखी जाए। मैसाचुसेट्स के एक जज ने उन राज्यों में मिड-टर्म चुनाव के लिए इस योजना पर रोक लगा दी। एक अपील्स कोर्ट ने उनके फ़ैसले को सही ठहराया। बाद में उन्होंने इसे पूरे देश में रोकने का दूसरा आदेश भी दिया, जो ट्रंप प्रशासन की योजना के लिए एक और संभावित बाधा बन सकता है।

राज्यों ने बहुत जल्दी मुकदमा किया

जुलाई के आखिर में जस्टिस डिपार्टमेंट ने प्रक्रिया से जुड़े आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की और तर्क दिया कि राज्यों ने बहुत जल्दी मुकदमा कर दिया। उन्होंने वॉशिंगटन के एक और फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें एक जज ने ट्रंप के आदेश को आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी। एक अपीलीय अदालत ने उस फैसले का समर्थन किया, साथ ही अगर बदलाव लागू किए जाते हैं तो भविष्य में अदालती कार्रवाई की गुंजाइश भी बनाए रखी।

फेडरल वकीलों ने तर्क दिया कि मैसाचुसेट्स का आदेश नवंबर में होने वाले फेडरल चुनावों के लिए चुनाव की निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रपति की प्रस्तावित नीतियों को अंतिम रूप देने और लागू करने की सरकार की क्षमता को रोकता है। रिपब्लिकन झुकाव वाले लगभग एक दर्जन राज्यों ने हाई कोर्ट में अपनी अपील में फेडरल सरकार का समर्थन किया और कहा कि अंतिम वोटर लिस्ट पर राज्यों की भी राय ली जाएगी।

मेल वोटिंग को जिम्मेदार ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मेल-इन बैलेट पर ट्रंप के समर्थन वाले तर्कों के खिलाफ फैसला सुनाया है और जून में यह माना था कि राज्य चुनाव के दिन के बाद आने वाले बैलेट की गिनती कर सकते हैं। वह मामला पूरी ब्रीफिंग और बहस के बाद तय किया गया था, न कि कोर्ट के इमरजेंसी डॉकेट पर। ट्रंप ने 2020 में डेमोक्रेट जो बाइडन से अपनी हार के लिए- बिना किसी ठोस सबूत के मेल वोटिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में प्रस्तावित बदलावों को गैर-अमेरिकी नागरिकों को वोट देने से रोकने के उपाय के तौर पर पेश किया है।

उन्होंने बार-बार ऐसे कानून को पास करने पर जोर दिया है, जिसके तहत वोट देने के लिए नागरिकता का सबूत देना ज़रूरी हो। गैर-नागरिकों का वोट देना बहुत कम देखा गया है, और यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए देश से निकाला जा सकता है।

दोनों पार्टियों के वोटरों के बीच लोकप्रिय

फेडरल डेटा के अनुसार, मेल बैलेट का इस्तेमाल दोनों पार्टियों के वोटरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डाले गए कुल बैलेट में से लगभग 30 प्रतिशत इसी तरह डाले गए थे। यह प्रक्रिया सुरक्षित भी है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 2025 की एक स्टडी में पाया गया कि हर 10 मिलियन मेल बैलेट में धोखाधड़ी के केवल चार मामले सामने आए।

तेल सप्लाई के लिए यूएई ने तैयार किया नया ठिकाना, यहां ईरान की मिसाइल भी नहीं पहुंच पाएगा

तेल अवीव, एजेंसी। पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी सैन्य तनाव के बीच UAE ने अपनी तेल सप्लाई और कारोबार को सुरक्षित रखने की दिशा बहुत बड़ा फैसला किया है। UAE के फुजैराह अमीरात और इजिप्ट (मिस्त्र) ने मिलकर भूमध्य सागर के तट पर स्थित न्यू अलामीन में एक नया ऑयल और गैस हब तैयार किया है।

करीब 7।38 लाख वर्ग मीटर में फैले इस प्राइवेट फ्री जोन में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टोरेज और ट्रेडिंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट फुजैराह अलामीन ऑयल एंड गैस कंपनी के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए इजिप्ट की कैबिनेट नेस्पेशल फ्री जोन को मंजूरी दी थी। अब कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है। मिस्त्र के आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, यह क्षेत्र न्यू अलामीन में अलेक्जेंड्रिया-मत्रूह तटीय सड़क के दक्षिणी हिस्से में है। इसका क्षेत्रफल करीब 737,914।9 वर्ग मीटर है।

फुजैराह के बाहर नया तेल ठिकाना क्यों?

फुजैराह पहले से ही मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल स्टोरेज और ट्रेडिंग केंद्रों में शामिल है। यहां तेल भंडारण की स्टोरेज की क्षमता बहुत अच्छी है। साथ ही अंतराष्ट्रीय समुद्री मार्गों तक भी सीधी पहुंच है। दरअसल, पश्चिमी एशिया में जारी लगातार सैन्य तनाव के बीच यह कहा जा रहा है कितेल कारोबार को सिर्फ एक जगह पर केंद्रित रखना जोखिम भरा हो सकता है। मिस्त्र के न्यू अलामीन में यह नया हब अल-हमरा पेट्रोलियम पोर्ट के आसपास विकसित किया जा रहा है। मिस्त्र के पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, इस साझेदारी से बंदरगाह की मौजूदा क्षमता और अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार को मजबूत करना है।

ईरान की जद से दूर क्यों यह नय तेल ठिकाना

UAE का इस प्रोजेक्ट दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि मिस्त्र में बना नया हब ईरानी मिसाइलों की पहुंच से तकरीबन बाहर है। हालांकि, ऐसा आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। लेकिन फुजैराह की तुलना में न्यू अल-अमीन खाड़ी क्षेत्र से काफी दूर, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव के बीच परियोजना तेल सप्लाई चेन के भौगोलिक जोखिम को कम करने के लिहाज से अहम हो सकती है। इसका साफ अर्थ है अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या किसी समुद्री मार्ग पर दबाव पड़ता है, तो तेल के स्टोरेज और ट्रेडिंग के लिए UAE और उसके साझेदारों के पास भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भी एक और विकल्प मौजूद होगा।

सिर्फ स्टोरेज नहीं, मिरुको भी फायदा

मिस्त्र इस परियोजना के जरिए देश अपने बंदरगाहों, समुद्री मार्गों और भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल कर खुद को ऊर्जा उत्पादों के स्टोरेज और ट्रेडिंग के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है।इजिप्ट के लिए यह प्रोजेक्ट विदेशी निवेश के साथ-साथ अपने पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का मौका भी है।

इस प्रोजेक्ट में 100% एक्सपोर्ट की शर्त क्या बताती है?

इस फ्री जोन की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है कि कंपनी को अपना पूरा वार्षिक उत्पादन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजना होगा। परियोजना का फोकस सिर्फ मिस्त्र की घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं।, बल्कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड है। न्यू अलामीन को एक ऐसे लॉजिस्टिक पॉइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां तेल को स्टोर कर जरूरत के हिसाब से अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सके।

भिलाई नगर चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

रायपुर। भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़े निर्वाचन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से संबंधित निर्वाचन याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई और ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।

मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। देवेंद्र यादव की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए SLP (Civil) No. 28778/2026 दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

प्रेम प्रकाश पांडेय ने दायर की है निर्वाचन याचिका

यह पूरा मामला 65-भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2023 के चुनाव परिणाम से जुड़ा है। भाजपा नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने निर्वाचन याचिका क्रमांक 9/2024 के माध्यम से देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है।

निर्वाचन याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के दौरान दाखिल किए गए शपथ-पत्र में कानून के तहत आवश्यक जानकारी का समुचित रूप से खुलासा नहीं किया गया। इसके अलावा याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण से संबंधित आरोप भी लगाए गए हैं।

इन आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। निर्वाचन याचिका में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों और आपत्तियों के समर्थन में साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

मुद्दों को प्रारंभिक स्तर पर तय कराने की थी मांग

निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें निर्वाचन मामले के मुद्दा क्रमांक 2 और 4 को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय करने की मांग की गई थी।

ये मुद्दे मुख्य रूप से नामांकन के शपथ-पत्र में आवश्यक जानकारी के प्रकटीकरण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 से संबंधित थे।

देवेंद्र यादव की ओर से इन मुद्दों पर प्रारंभिक स्तर पर ही निर्णय लेने की मांग की गई थी। हालांकि, 30 जून 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित मुद्दे केवल कानून के प्रश्न नहीं हैं, बल्कि इनमें तथ्य और कानून दोनों से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। ऐसे मामलों का उचित परीक्षण साक्ष्य दर्ज होने के बाद नियमित ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे देवेंद्र यादव

हाईकोर्ट के इसी आदेश को देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके लिए उन्होंने SLP (Civil) No. 28778/2026 दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और SLP खारिज कर दी। इसका सीधा असर यह है कि निर्वाचन याचिका अब हाईकोर्ट में नियमित ट्रायल और साक्ष्य की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगी।

यानी जिन मुद्दों को प्रारंभिक स्तर पर तय कराने की मांग की गई थी, उनका परीक्षण अब मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे देवेंद्र यादव

भिलाई नगर निर्वाचन विवाद में यह देवेंद्र यादव की सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महत्वपूर्ण SLP है, जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली है।

इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 5 जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए SLP (Civil) No. 6306/2025 दाखिल की थी। यह मामला भी देवेंद्र यादव बनाम प्रेम प्रकाश पांडेय के नाम से सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में इस मामले की पुष्टि होती है।

इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती CPC के आदेश VII नियम 11 से संबंधित कार्यवाही को लेकर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में इस मामले पर सुनवाई की थी और बाद में याचिका खारिज कर दी थी।

अब हाईकोर्ट में होगा निर्वाचन याचिका का ट्रायल

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा मूल निर्वाचन विवाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में आगे बढ़ेगा।

अब मामले में दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और निर्वाचन याचिका में उठाए गए कानूनी एवं तथ्यात्मक मुद्दों की जांच ट्रायल के दौरान होगी। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाचन याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित हो गए हैं या देवेंद्र यादव का निर्वाचन रद्द हो गया है। निर्वाचन याचिका के मूल विवाद पर अंतिम निर्णय अभी हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

भिलाई नगर विधानसभा सीट के वर्ष 2023 के चुनाव परिणाम से जुड़े इस मामले पर अब सबकी नजर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया पर रहेगी।

दृश्यम 3 की सक्सेस के बाद दृश्यम 4 का ऐलान, मोहनलाल फिर बनेंगे जॉर्जकुट्टी

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी दृश्यम को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। अब तक इसके तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं और तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। खास बात यह है कि हर पार्ट के साथ जॉर्जकुट्टी की कहानी को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ती गई। अब दृश्यम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मेकर्स ने फ्रैंचाइजी के चौथे पार्ट यानी दृश्यम 4 पर मुहर लगा दी है। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस एक बार फिर जॉर्जकुट्टी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं।

प्रोड्यूसर एंटनी पेरुम्बावूर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में दृश्यम फ्रैंचाइजी के चौथे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि फ्रैंचाइजी का अगला पार्ट जरूर बनाया जाएगा और इस पर काम शुरू किया जा रहा है।

हालांकि, फिल्म की कहानी और रिलीज डेट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म में मोहनलाल एक बार फिर अपने मशहूर किरदार जॉर्जकुट्टी के रूप में नजर आएंगे।

फिल्म के निर्देशक जीथू जोसेफ ने बताया था कि हर पार्ट के बाद मेकर्स उन पर अगला पार्ट बनाने का दबाव डालते हैं। जीथू जोसेफ ने कहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि कहानी के बारे में सोचते रहो। पहली फिल्म के बाद उन्होंने कहा कि दूसरी के बारे में सोचो। फिर दूसरे पार्ट की शूटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि चलो तीसरा शुरू करते हैं और अब वो कह रहे हैं कि चौथे पार्ट पर काम करना चाहिए। सिर्फ फिल्म की सफलता को देखते हुए जल्दबाजी में अगला पार्ट नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं कहानी और किरदारों पर पूरा समय देना चाहता हूं, ताकि अगली फिल्म भी दर्शकों को पसंद आए।

दृश्यम की कहानी एक आम आदमी जॉर्जकुट्टी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। फिल्म में परिवार, सस्पेंस और क्राइम को जिस तरह से दिखाया गया, उसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। मोहनलाल ने जॉर्जकुट्टी के किरदार में अपनी दमदार एक्टिंग से कहानी में जान डाल दी। फिल्म की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे दूसरे देशों में भी काफी पसंद किया गया।

दृश्यम की सफलता के बाद इस मलयालम फिल्म के कई भाषाओं में रीमेक बनाए गए। हिंदी में अजय देवगन स्टारर दृश्यम और दृश्यम 2 को भी दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला। दोनों फिल्मों में अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया था। हिंदी वर्जन की सफलता ने भी इस कहानी को देशभर में और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। अब दर्शक दृश्यम 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

बता दें कि दृश्यम 3 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, कलाभवन शजोहन, सिद्दीकी, मुरली गोपी और आशा शरथ जैसे एक्टर्स नजर आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में 249 करोड़ रुपये जुटाए थे। फिल्म की कमाई ने एक बार फिर साबित किया कि जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी को देखने में दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है।

वहीं, दृश्यम फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म 19 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म में मोहनलाल ने जॉर्जकुट्टी का किरदार निभाया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 62 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म की कहानी, सस्पेंस और मोहनलाल की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद फिल्म का सीक्वल दृश्यम 2 साल 2021 में सिनेमाघरों की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। दूसरे पार्ट में भी मोहनलाल और बाकी कलाकारों ने अपने पुराने किरदारों को आगे बढ़ाया था। दोनों फिल्मों की सफलता के बाद ही दृश्यम एक बड़ी क्राइम-थ्रिलर फ्रैंचाइजी बन गई।

धनुष-करीना की जोड़ी पर लगी मोहर, संजय लीला भंसाली की फिल्म में होगा बड़ा धमाका

हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनने वाली एक हिंदी फिल्म के लिए करीना कपूर से संपर्क किया गया है। धनुष का नाम फिल्म के लिए पहले ही तय हो चुका है। अब फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्देशक एस मिथरन ने एक हालिया इंटरव्यू में पुष्टि की है कि धनुष और करीना का नाम फिल्म के लिए लगभग तय है।

निर्देशक बोले, बातचीत अभी जारी है और दोनों कलाकारों की तारीखों को देखा जा रहा है, ताकि उनकी उपलब्धता की पुष्टि की जा सके।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ अच्छी खबर सामने आएगी। फिल्म को लेकर अगस्त की शुरुआत से ही बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा में चर्चा तेज है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बड़े स्तर पर बनाई जाने वाली पौराणिक जंगल एडवेंचर फिल्म होगी, जिसे लेकर दर्शकों में भी उत्सुकता बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म फिलहाल लेखन के चरण में है और इसकी स्क्रिप्ट को फाइनल करने से पहले कई बार दोबारा लिखा जा चुका है।

निर्माता प्रोजेक्ट को लेकर काफी तैयारी कर रहे हैं। फिल्म का प्री-प्रोडक्शन नवंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि इसकी मुख्य शूटिंग जनवरी 2027 में शुरू हो सकती है।

अगर फिल्म तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ती है तो ये मिथरन की बॉलीवुड में बतौर निर्देशक पहली फिल्म होगी।

इस फिल्म के जरिए करीना- भंसाली करीब 2 दशक बाद पहली साथ काम करेंगे। उनके बीच 2000 के दशक की शुरुआत में अनबन की खबरें आई थीं। भंसाली ने फिल्म देवदास में पारो के रोल के लिए करीना से बात की थी और उनका स्क्रीन टेस्ट भी लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को पारो के रोल के लिए चुन लिया।

इस बात से करीना काफी नाराज हुई थीं। उन्होंने भंसाली के फैसले को गलत बताया था।

करीना जल्द ही फिल्म दायरा में भी नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं, जबकि इसमें करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में हैं।

दायरा की कहानी और कलाकारों की जोड़ी इसे खास बनाती है। ये फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

दायरा सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें अपराध, कानून, न्याय और सजा जैसे मुद्दों को दिखाया जाएगा

नेटफ्लिक्स पर दिखेगा तापसी पन्नू का गंधारी रूप, बेटी को बचाने के लिए मां करेगी सारी हद पार

तापसी पन्नू को आखिरी बार फिल्म अस्सी में देखा गया था, जो इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई। अब अभिनेत्री अपनी अगली और लंबे समय से चर्चित फिल्म गांधारी के साथ दर्शकों के बीच लौट रही हैं। यह एक हाई-वोल्टेज एक्शन, क्राइम और बदले पर आधारित थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। कहानी कनिका ढिल्लों ने लिखी है और उन्हीं के बैनर कथा पिक्चर्स के तहत निर्मित है। फिल्म सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी।

गांधारी का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। यह 3 सितंबर, 2026 से सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

फिल्म में तापसी मुख्य किरदार में हैं। उनके साथ इश्वाक सिंह, स्वास्तिका मुखर्जी, छाया कदम, जतिन सरना और मीता वशिष्ठ जैसे कलाकार मौजूद हैं।

कहानी एक मां-बेटी के गहरे और अटूट रिश्ते पर आधारित है। मां के किरदार में तापसी हैं, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभिनेत्री बिल्कुल नए अवतार में दिखेंगी।

गंधारी में तापसी के अलावा इश्वाक सिंह, छाया कदम, स्वास्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और जतिन सरना जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

फिर आई हसीन दिलरुबा की शानदार सफलता के बाद, इस फिल्म से तापसी और लेखिका और निर्माता कनिका ढिल्लों की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है।

कनिका ने बानी के इस सफर को एकदम असली, अथक और बेहद निजी बताया है। वहीं, नेटफ्लिक्स ने कहा है कि यह फिल्म इस बात पर एक बेबाक नजर डालेगी कि एक मां अपने बच्चे के लिए कितनी हद तक जा सकती है।

तापसी भी इसमें अपने अब तक के सबसे चुनौती भरे किरदारों में से एक में नजर आने वाली हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com